सान्ध्य हिन्दी दैनिक

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

वर्ष - 03	अंक - 99	जौनपुर, शुक्रवार, 29 नवम्बर 2024	सान्ध्य दैनिक (संस्करण)	पेज - 4	मूल्य - 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

भारत की बड़ी कामयाबी, मोस्ट वांटेड आतंकी को रवांडा से लाया गया भारत

नई दिल्ली,(एजेंसी)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बेंगलुरु स्थित आतंकवादी मॉड्यूल को धन और हथियार और गोला–बारूद मुहैया कराने के आरोपी लश्कर–ए–तैयबा (एलईटी) से जुड़े एक आतंकवादी को रवांडा से प्रत्यर्पित किया है। अधिकारियों के अनुसार, सलमान रहमान खान का प्रत्यर्पण किगाली में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और इंटरपोल के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के सहयोग से सीबीआई के ग्लोबल ऑपरेशंस सेंटर द्वारा किए गए एक बेहद गोपनीय ऑपरेशन का हिस्सा था। खान पर आपराधिक साजिश में शामिल होने, आतंकवादी संगठन में सदस्यता लेने और पाकिस्तान स्थित लश्कर–ए–तैयबा को सामग्री सहायता प्रदान करने का आरोप है। एनआईए ने 2023 में उसके खिलाफ शस्त्र अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और आतंकवाद से संबंधित विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया। उस पर बेंगलुरु में आतंकवादी गतिविधियों के लिए हथियार, गोला–बारूद और विस्फोटकों की आपूर्ति में मदद करने का आरोप है ।

कोलकाता में 2.99 लाख रुपये मूल्य की नकली मुद्रा जब्त

उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए कोलकाता पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) ने कोलकाता के मध्य भाग में धर्मतला बस स्टैंड क्षेत्र से व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया, ''व्यक्ति के पास से 500 रुपये के एफआईसीएन के छह बंडल जब्त किए गए। ऐसा लगता है कि व्यक्ति नकली नोट की आपूर्ति करने वाले गिरोह का सदस्य है। उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उसे आज स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा।'' अधिकारी ने बताया कि आरोपी मालदा जिले का निवासी है और मामले की जांच जारी है।

शिव मंदिर बताने वाली याचिका मंजूर, शुरू हुई सियासत

उत्तर प्रदेश में संभल जिला जहां शाही जामा मस्जिद के अदालत के आदेश पर किए गए सर्वेक्षण के बाद तनाव देखने को मिला। वहीं अब राजस्थान के अजमेर की एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को प्रसिद्ध अजमेर शरीफ दरगाह के सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका पर केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और अजमेर दरगाह समिति को नोटिस जारी किया। याचिका हिंदू सेना प्रमुख विष्णु गुप्ता द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने दावा किया था कि अजमेर शरीफ दरगाह में काशी और मथुरा की तरह एक मंदिर था। वादी विष्णु गुप्ता के अधिवक्ता योगेश सिरोजा ने अजमेर में संवाददाताओं को बताया कि वाद पर दीवानी मामलों के न्यायाधीश मनमोहन चंदेल की अदालत में सुनवाई हुई। सिरोजा ने कहा कि दरगाह में एक शिव मंदिर होना बताया जा रहा है। उसमें पहले पूजा पाठ होता था३ पूजा पाठ दोबारा शुरू करवाने के लिये वाद सितंबर 2024 में दायर किया गया।

पहली बार प्रधानमंत्री गंगा पूजन कर महाकुंभ की करेंगे शुरुआत, 13 दिसंबर को आएंगे पीएम मोदी

प्रयागराज । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को खुद गंगा पूजन कर महाकुंभ–2025 की शुरुआत करेंगे। ऐसा पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री महाकुंभ आयोजन की शुरुआत करेंगे। इससे पहले आमतौर पर डीएम या मेलाधिकारी ही गंगा पूजन कर माघ मेला या कुंभ की शुरुआत करते रहे हैं। बुधवार को प्रयागराज आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी जानकारी देने के महाकुंभ एवं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री 13 दिसंबर को प्रयागराज आएंगे। संगम से पहले उनका शृंग्वेरपुर धाम में कार्यक्रम प्रस्तावित है। वहां निषादराज पार्क, भगवान राम एवं निषादराज की गले मिलते प्रतिमा, घाट का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद अरैल पहुंचेंगे और वहां से निषादराज क्रूज से संगम आएंगे। संगम नोज पर आयोजित सभा में प्रधानमंत्री साढ़े छह हजार करोड़ रुपये लागत की 150 से अधिक निर्माण परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री गंगा पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के लिए क्विज की घोषणा की है। क्विज के जरिये युवा ऐतिहासिक विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का हिस्सा बन सकेंगे। प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में यह उनका अमिट योगदान होगा। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में युवाओं से कहा, यह आपके विचारों को सरकार के सर्वोच्च स्तर तक सुनने का एक बहुत ही विशेष अवसर है। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन अगले साल 11–12 जनवरी को होना है।

चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन, मंच पर दिखी इण्डिया ब्लॉक की ताकत

झारखंड,(एजेंसी)। मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) नेता हेमंत सोरेन ने गुरुवार को रांची में झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सोरेनी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में सोरेन का यह चौथा कार्यकाल है। सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी अगली पारी से पहले अपने पिता और पार्टी संस्थापक शिबू सोरेन से आशीर्वाद लिया। झारखंड के मुख्यमंत्री के शपथ समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, राजद नेता तेजस्वी यादव, कांग्रेस नेता तारिक अनवर, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव सहित विपक्ष के कई शीर्ष नेता शामिल हुए।

झारखंड के 14वें सीएम के रूप में हेमंत सोरेन के शपथ लेने के बाद उनकी बहन और जेएमएम नेता अंजनी सोरेन का कहना है, आज पूरा झारखंड खुश है... हमें पहले से ही यह उम्मीद थी कि हम पूर्ण बहुमत से जीतेंगे ।ष

बंगाल सरकार 'स्वास्थ्य साथी' योजना के तहत खर्च में वृद्धि की जांच कर रही है : ममता बनर्जी

कोलकाता । पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक चिकित्सक के साथ कथित बलात्कार और हत्या की घटना के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान राज्यभर में 'स्वास्थ्य साथी' योजना के तहत खर्च में बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद सरकार को मामले की जांच करानी पड़ी। बनर्जी ने विधानसभा में कहा, ''उस समय (आरजी कर अस्पताल की घटना के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान) 'स्वास्थ्य साथी' योजना के तहत खर्च में भारी वृद्धि हुई थी। हम जांच

कर रहे हैं। दोषियों को सजा दी जाएगी।'' एक सर्वेक्षण से पता चला है कि पीड़ित महिला चिकित्सक के लिए न्याय की मांग को लेकर कनिष्ठ चिकित्सकों के प्रदर्शन के दौरान निजी अस्पतालों में 'स्वास्थ्य साथी' योजना के तहत मरीजों के इलाज पर राज्य के खर्च में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। 'स्वास्थ्य साथी' योजना राज्य सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसके तहत प्रति परिवार को चिकित्सा देखभाल के लिए प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये तक की आर्थिक मदद मिलती है।

दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर केंद्र पर बरसे केजरीवाल

एक धमाका भी हो गया, गृहमंत्री जी, नींद से जागिए

नई दिल्ली,(एजेंसी)। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में शबिगड़तीश कानून व्यवस्था को लेकर केंद्र की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर सवाल उठाया। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा करने में विफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होती जा रही है। पिछले 1–1.5 साल से दिल्ली में अपराध बढ़ रहे हैं। व्यापारियों को रंगदारी के लिए फोन आ रहे हैं, हत्या और छेड़छाड़ के मामले बढ़ रहे हैं। आप नेता ने कहा कि कई सालों के बाद दिल्ली में गैंगवार देखने को मिल रही है। आज लोग कहते हैं कि दिल्ली दुनिया की सबसे असुरक्षित राजधानी है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि दिल्ली में मर्डर, रंगदारी, लूट और लगातार बढ़ते क्राइम से जनता पहले से ही डर के साये में है और आज एक धमाका भी हो गया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आराम से और सुरक्षित जीने का सबको अधिकार है। गृहमंत्री अमित शाह जी, कृपया नींद से जागिए और अपनी जिम्मेदारी निभाइए। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के घर से चंद किलोमीटर दूर महिलाओं के साथ खध्तरनाक घटनायें हो रही हैं लेकिन अमित शाह जी कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमित शाह जी, आप अरविंद केजरीवाल को नहीं अपराध और गुंडों को रोकिए। दिल्ली में व्यापारियों को खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं और गोलियां चलाई जा रही हैं। आज वह डरकर दिल्ली छोड़ रहे हैं। दिल्ली में व्यापार करना कठिन हो गया है। आप प्रमुख ने विशेष रूप से अपराधों को संबोधित करने और निवासियों को सुरक्षा की भावना प्रदान करने में केंद्र सरकार की ओर से कार्रवाई की कमी पर भी निराशा व्यक्त की। उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में गृह मंत्री अमित शाह के आवास के आसपास अपराध की घटनाओं को दर्शाने वाला एक नक्शा साझा किया। दिल्ली पुलिस (कानून एवं व्यवस्था) केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आती है। केजरीवाल की यह टिप्पणी फरवरी में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आई है। आप ने दिल्ली में पिछले दो विधानसभा चुनावों में भारी बहुमत से जीत हासिल की है।आज एक धमाका भी हो गया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आराम से और सुरक्षित जीने का सबको अधिकार है। गृहमंत्री अमित शाह जी, कृपया नींद से जागिए और अपनी जिम्मेदारी निभाइए। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के घर से चंद किलोमीटर दूर महिलाओं के साथ खध्तरनाक घटनायें हो रही हैं लेकिन अमित शाह जी कुछ नहीं कर रहे हैं।

कुछ बड़ा होने वाला है! बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म के बीच पीएम मोदी से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर

नई दिल्ली,(एजेंसी)। पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार दोपहर पीएम मोदी से मुलाकात की। सूत्रों ने कहा कि अगर दोनों संसद भवन सुचारू रूप से चले तो जयशंकर जल्द ही इस मामले पर बयान देंगे। स्थगित होने के बाद संसद में

बैठक हुई, जिसमें बांग्लादेश में उभरती स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया गया। 25 नवंबर को ढाका हवाई अड्डे पर हिंदू भिक्षु चिन्मय कृष्ण दास प्रभु की गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। एक वकील सैफुल इस्लाम अलिफ की हत्या कर दी गई, जब चटगांव में एक अदालत के बाहर हजारों लोग गिरफ्तार हिंदू भिक्षु चिन्मय की रिहाई की मांग कर रहे थे। कृष्ण दास प्रभु, जिन्हें बाद में जमानत देने से इनकार कर दिया गया और देशद्रोह के आरोप में जेल भेज दिया गया। प्रभु इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस (इस्कॉन) के सदस्य थे और हाल ही में उन्हें निष्कासित कर दिया गया था। उन्हें मंगलवार को जमानत देने से इनकार कर दिया गया, जिसके कारण हिंदू समुदाय ने और अधिक विरोध प्रदर्शन किया, जिन्होंने यूनुस प्रशासन के तहत उनके खिलाफ अत्याचार का हवाला दिया।

हमने कभी दिल्ली से कभी भीख नहीं मांगी : संजय राउत

नई दिल्ली,(एजेंसी)। शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने गुरुवार को पुष्टि की कि महाराष्ट्र में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति की शानदार जीत के बाद विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) में कोई दरार नहीं है। उन्होंने अफवाहों को निराधार बताया और पुष्टि की कि उद्धव सेना एमवीए नहीं छोड़ रही है। 23 नवंबर को महायुति ने राज्य चुनाव में 288 विधानसभा सीटों में से 230 सीटें जीतकर परचम लहराया। भाजपा 132 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जो अब तक की उसकी सबसे बड़ी संख्या है, जबकि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजीत पवार की राकांपा को क्रमशः 57

और 41 सीटें मिलीं। आज एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, राउत ने कहा कि इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व वाला गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनावों में एक साथ लड़ने में सफल रहा। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद अगर कोई यह (अफवाह) कहता है, तो यह उनकी निजी राय हो सकती है। जब हम आम चुनाव जीते थे, तो किसी ने नहीं कहा कि उद्धव सेना को गठबंधन से अलग हो जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि आप लोग चिंतित क्यों हैं? अभी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं... हम देखेंगे, हमें पता है कि क्या करना है। इसके साथ ही राउत ने महायुति पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनके (महायुति) पास पूर्ण बहुमत है। 7 दिन बाद भी महायुति महाराष्ट्र को सीएम नहीं दे पाई है। कारण क्या है? पीएम, अमित शाह और उनके नेता अपना सीएम क्यों नहीं तय कर सकते? वह (एकनाथ शिंदे) बालासाहेब ठाकरे का नाम लेते हैं और शिवसेना के नाम पर राजनीति करते हैं लेकिन उनके फैसले दिल्ली में होते हैं। उन्होंने कहा कि बाला साहेब ठाकरे की शिव सेना का भविष्य कभी दिल्ली में तय नहीं हुआ, ये मुंबई में तय हुआ। हम कभी दिल्ली नहीं गए, वहां अटल जी और आडवाणी जी होते थे। हमने कभी दिल्ली जाकर उनके सामने भीख नहीं मांगी।

जब राज्यसभा में प्रमोद तिवारी को जगदीप धनखड़ ने दी सलाह

नई दिल्ली,(एजेंसी)। संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र के बीच राज्यसभा की कार्यवाही के लगातार स्थगित होने के बाद, उच्च सदन के सभापति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को हंगामा करने और ष्सार्थक बातचीत का अवसरष चूकने पर सांसदों को समझाया। विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सांसदों के हंगामे के बाद गुरुवार को राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। शुक्रवार को सुबह 11 बजे सदन की बैठक दोबारा होगी। शीतकालीन सत्र के चौथे दिन सदन के अंदर हुए हंगामे पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जगदीप धनखड़ ने कहा कि सदन उस रचनात्मक भागीदारी से चूक गया जो लोगों की सामूहिक आकांक्षा को प्रतिध्वनित करती। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश के एक सवाल पर ष्हम आसन को कैसे मना सकते हैं?ष इसके जवाब में जगदीप धनखड़

ने ने कहा कि हम ऐतिहासिक रूप से नियमों के अनुपालन के उच्चतम मानक का प्रदर्शन करके ही अध्यक्ष को राजी करते हैं। और जैसा कि मैंने कल संकेत दिया था, अध्यक्ष के फैसले से सम्मान पैदा होना चाहिए न कि चुनौती। सदन के महत्व और राष्ट्र निर्माण में इसकी भूमिका पर जोर देते हुए सभापति ने कहा, ''यह सदन सिर्फ बहस के सदन से कहीं अधिक है। हमारी राष्ट्रीय भावना यहीं से गूंजनी है। संसदीय व्यवधान कोई उपाय नहीं है, यह एक राग है, यह हमारी नींव को कमजोर करता है... हमें आपकी प्रासंगिकता बरकरार रखनी चाहिए। उन्होंने सांसदों से राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए अर्थ संवाद में शामिल होने का भी आग्रह किया। उन्होंने आगे कहा कि माननीय सदस्यों, जब हम इस प्रकार के आचरण में संलग्न होते हैं, तो हम संवैधानिक नियमों से भटक जाते हैं। हम अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ते हैं। राष्ट्रवाद को पोषित करना हमारा कर्तव्य है।श मैं आप सभी से सार्थक संवाद की भावना को अपनाने का आग्रह करता हूं। उन्होंने कहा कि हमें संविधान की भावना का अपमान नहीं करना चाहिए। इसके तत्काल बाद कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने नोटिस खारिज किए जाने के बाद व्यवस्था का प्रश्न उठाया और अदाणी मुद्दे पर चर्चा की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि यह बेहद गंभीर मुद्दा है और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। सभापति धनखड़ ने तिवारी से कहा कि उनकी कोई भी बात रिकार्ड में नहीं जाएगी। प्रमोद तिवारी ने चेयरमैन की ओर इशारा करते हुए कहा कि सर आपके बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता है। इस पर जगदीप धनखड़ ने टोकते हुए।

वायनाड से जीत के बाद प्रियंका गांधी ने सांसद के रूप में शपथ ली

केरल,(एजेंसी)। हाथ में संविधान की किताब लिए 52 वर्षीय प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और संसद में बैठे सांसदों की मौजूदगी में शपथ ली। उनके पति रॉबर्ट वाड्रा और उनके बच्चे, और कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे निचले सदन की गैलरी में मौजूद थे। प्रियंका गांधी वाड्रा के लोकसभा में प्रवेश के साथ, संसद में अब दशकों में पहली बार गांधी परिवार के तीन सदस्य हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी जहां लोकसभा में बैठेंगे, वहीं उनकी मां सोनिया गांधी 2024 के लोकसभा चुनावों में रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ने का विकल्प चुनने के बाद राज्यसभा में हैं। वायनाड और रायबरेली दोनों से जीतने वाले राहुल गांधी ने अपने पारिवारिक गढ़ को बरकरार रखने का फैसला किया और वायनाड को खाली कर दिया, जिसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा को वहां से मैदान में उतारा गया। उन्हें 6.22 लाख वोट मिले और उन्होंने अपने निकटतम सीपीएम प्रतिद्वंद्वी सत्यन मोकेरी को चार लाख से अधिक वोटों से हराया,

जो 2024 के चुनावों में राहुल गांधी को मिले वोटों से अधिक है। अपनी जीत के बाद, प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि वह संसद में लोगों की आवाज बनने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने ट्वीट किया, ष्आपने मुझ पर जो भरोसा जताया है, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि समय के साथ, आपको वास्तव में यह महसूस हो कि यह जीत आपकी जीत है और जिस व्यक्ति को आपने अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना है, वह आपकी उम्मीदों और सपनों को समझता है और आपके लिए लड़ता है। मैं संसद में आपकी आवाज बनने के लिए उत्सुक हूं।ष राहुल गांधी ने वायनाड में 3.64 लाख वोटों के अंतर से 6.47 लाख वोट हासिल करते हुए भारी जीत हासिल की। घ्उन्होंने 2019 और 2024 के चुनावों में दो बार इस निर्वाचन क्षेत्र पर कब्जा किया। प्रियंका गांधी वाड्रा के अलावा, कांग्रेस नेता रवींद्र चव्हाण, जिन्होंने नांदेड़ सीट पर हुए लोकसभा उपचुनाव में अपने भाजपा प्रतिद्वंद्वी को हराया था, ने भी सांसद के रूप में शपथ ली। प्रियंका गांधी वाड्रा ने 2019 में पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रभारी कांग्रेस महासचिव नियुक्त किए जाने के बाद राजनीति में प्रवेश किया। एक साल बाद, उन्हें पूरे राज्य की जिम्मेदारी सौंपी गई।

संपादकीय

बांग्लादेश का इतिहास

बांग्लादेश में हसीना सरकार के पतन और उनके भारत में शरण लेने के बाद अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं पर जिस तरह लगातार हमले हो रहे हैं, इस्कॉन से जुड़े धर्मगुरु चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी उसकी अगली कड़ी है। दास की जमानत याचिका खारिज होने के बाद उनके वकील की निर्मम हत्या असहिष्णुता की पराकाष्ठा को ही दर्शाती है। इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि वहां अल्पसंख्यक किन भयावह स्थितियों का सामना कर रहे हैं। इतना ही नहीं धर्मगुरु चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे लोगों पर हमले तक किए गए। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के पैरोकार दास को कथित रूप से बांग्लादेशी झंडे का अपमान करने तथा राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उनकी गिरफ्तारी और जमानत न दिए जाने के कारण बांग्लादेश और सीमा पार भारत में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए हैं। दरअसल, इस अशांति का संदर्भ लगातार अल्पसंख्यक उत्पीड़न के पैटर्न में निहित हैं। बांग्लादेश के संवैधानिक आश्वासन के बावजूद वहां के हिंदू, जो कि आबादी का लगभग नौ फीसदी हैं, लगातार हिंसा, बर्बरता और सामाजिक उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। वहां हिंदुओं के घरों व मंदिरों पर भीड़ पर हमलों की खबरें चिंता बढ़ाने वाली हैं। जिसमें हसीना सरकार के पतन के बाद खासी तेजी आई है। आधिकारिक रूप से इस्लामिक धर्म वाले इस देश में यह स्थिति अल्पसंख्यकों की व्यापक असुरक्षा को दर्शाती है। अल्पसंख्यक संगठनों द्वारा सुरक्षा की गुहार लगाये जाने के बाद विश्वास बहाली की जिम्मेदारी कार्यवाहक सरकार पर है। जिसका दायित्व बनता है कि उत्पीड़न के शिकार लोगों को न्याय दिलाने के लिये विशेष न्यायाधिकरण के जरिये यथाशीघ्र कार्रवाई करे। यदि समय रहते ऐसा नहीं होता तो अशांति के बढ़ने का खतरा बना रहेगा। मौजूदा घटनाचक्र से बांग्लादेश की प्रगतिशील लोकतंत्र की छवि कमजोर हुई है। निस्संदेह, वहां सभी अल्पसंख्यकों के लिये शांति और सुरक्षा एक जीवंत वास्तविकता होनी चाहिए। ढाका सरकार को छात्र आंदोलन के जरिये हुए राजनीतिक परिवर्तन के बाद पनप रही कट्टरता पर अंकुश लगाना चाहिए। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के लगातार उत्पीड़न के विरोध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीखी प्रतिक्रियाएं गाहे–बगाहे आती रही हैं। पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा पर गंभीर चिंता जतायी थी। यहां तक कि ट्रांसपेरंसी इंटरनेशनल ने भी अपनी हालिया रिपोर्ट में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के दौरान अल्पसंख्यकों पर बढ़े हमलों को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। रिपोर्ट में हसीना सरकार के पतन के बाद के एक पखवाड़े में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के दो हजार से अधिक मामलों का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट इस बात पर भी चिंता जताती है कि ऐसे मामलों में अपराधियों की पहचान होने के बावजूद उन्हें दंडित नहीं किया गया। बल्कि इसके बहाने राजनीतिक विरोधियों को ही निशाना बनाया गया। ऐसी हिंसा के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की तरफ से भी तल्ख प्रतिक्रिया दर्ज की गई है। यह विडंबना ही है कि जिस बांग्लादेश की स्थापना भारत के त्याग व बलिदान के चलते एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में हुई थी, आज वहां यूनस सरकार उन मूल्यों को ताक पर रख रही है। भारत सरकार के विरोध के बावजूद यूनस सरकार किसी भी तरह से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की गारंटी देने को तैयार नहीं है। बांग्लादेश का इतिहास बताता है कि जब–जब सेना के हाथ में सत्ता की बागडोर आई है, तो कट्टरपंथियों को संरक्षण मिला है। ऐसे में फौज द्वारा गठित अंतरिम सरकार से इस दिशा में किसी बड़ी पहल की उम्मीद करना बेमाने ही होगा। भारत सरकार को राजनीतिक व कूटनीतिक प्रयासों से अंतरिम सरकार पर दबाव बनाना होगा ताकि वह अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का आश्वासन दे। तभी कट्टरपंथियों की निरंतर जारी हिंसा पर अंकुश लगाने की उम्मीद की जा सकती है। इसके साथ ही पाक समर्थित कट्टरपंथी संगठनों पर भी नियंत्रण करने के लिये दबाव बनाने की जरूरत है। वैसे अंतरिम सरकार के अड़ियल रवैये को देखते हुए बहुत ज्यादा उम्मीद इस दिशा में नजर नहीं आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का दबाव इस दिशा में एक उपाय हो सकता है।

महिलाओं को 'सुरक्षित' रखने के लिए यूपी पैनल का प्रयास गलत प्रतीत होता है

एक राज्य के रूप में, यूपी काफी हद तक पारंपरिक है, जिसमें महिलाओं के प्रति विशेष रूप से प्रतिगामी दृष्टिकोण गहराई से जड़ जमाए हुए हैं। लेकिन अब इसे चुनौती दी जा रही है। पिछले दशक में लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा के लिए एक बड़े कदम के कारण, 2021 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार, लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा के आँकड़ों में 2017–19 के दौरान लगभग 2.48 मिलियन की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसी समय, कार्यबल से 6.3 मिलियन महिलाओं की पूर्ण गिरावट आई, जो शिक्षा में लड़कियों और महिलाओं की वृद्धि से 2.5 गुना अधिक है। इसके बावजूद, महिलाएँ अपने घरों से बाहर निकल रही हैं और जिम, योग कक्षाओं और अन्य गतिविधियों के लिए साइन अप कर रही हैं, और इसमें उनका पुरुषों के संपर्क में आना स्वाभाविक है। ।सेव त्मंक – कहानीरू स्वाभिमान और यह ज्यादातर पुरुष ही हैं जो इन व्यवसायों में काम करते हैं, जैसा कि दर्जी के साथ होता है। तो, महिलाओं को क्या करना चाहिए? पारंपरिक घरों में पली–बढ़ी और अक्सर लिंग के आधार पर अलग–अलग रहने वाली महिलाओं को पुरुषों के साथ बातचीत करना मुश्किल होगा। महिला आयोग जिस "बुरे स्पर्श" का उल्लेख करता है, उसे कुछ साल पहले नाबालिगों, खासकर लड़कियों के यौन उत्पीड़न की बढ़ती संख्या के बारे में बोलने के साथ लोकप्रिय बनाया गया था। यह हमारे निजी अंगों को अनुचित तरीके से छूने से संबंधित है। भारत में यह काफी आम बात है क्योंकि घर और सार्वजनिक स्थानों दोनों पर महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। सड़क पर, बसों, ट्रेनों और कार्यस्थलों पर उत्पीड़न होता है। बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून और इन मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के बावजूद, समस्याएँ बनी हुई हैं। बदलाव फिर भी, नीति निर्माताओं और जनता ने यह नहीं पूछा है कि ऐसा क्यों है और शायद कुछ और करने की कोशिश की जानी चाहिए। जागरूकता पैदा करने के लिए सबसे स्पष्ट जगह स्कूली पाठ्यक्रम है। अब इस पर पर्याप्त काम है जिसका उपयोग अध्यक्ष और आयोग यूपी में कक्षाओं के साथ–साथ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में इसे शुरू करने के लिए कर सकते हैं। भाजपा के महिला मोर्चा के कैडर अनुचित स्पर्श की प्रकृति के बारे में घर–घर जाकर प्रचार कर सकते हैं। किसी चीज पर प्रतिबंध लगाने से कभी कहीं काम नहीं हुआ। फिर एक छोटा सा सवाल यह है कि कितनी महिला जिम ट्रेनर, दर्जी और योग शिक्षक हैं? वही राज्य जो महिला सशक्तिकरण में विश्वास करने का दावा करता है, उसे अपने घरों और सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा करना मुश्किल लगता है। बच्चे को भेजना है घर से दूर महिलाओं को भी बाहरी दुनिया का सामना करते समय पुरुषों के साथ बातचीत करना सीखना होगा। यह आसान नहीं है, लेकिन जीवित रहने का यही एकमात्र तरीका है। ना कहना सीखना, संभावित उत्पीड़न के संकेतों को पहचानने में सक्षम होना और फिर आगे बढ़ने का फैसला करना ऐसे कौशल हैं । जिन्हें महिलाओं को सीखना होगा। कानून पर्याप्त निवारक नहीं हैं।

मैसाचुसेट्स की अदालत ने शादी की अंगूठियां लौटाने संबंधी दशकों पुराने कानून को पलट दिया

पैसे से प्यार नहीं खरीदा जा सकता। लेकिन कई लोगों के लिए, प्यार का इजहार करने के लिए बड़ी और महंगी हीरे की अंगूठी से बेहतर कुछ नहीं है। अपने साथी को बहुत ज़्यादा पैसे वाली कोई चीज उपहार में देना प्रतिबद्धता की निशानी के तौर पर देखा जाता है। ऐतिहासिक रूप से, ऐसा तोहफा पत्नी के लिए एक सहारा होता था, जब पति की मृत्यु हो जाती थी या वह उसे छोड़ देता था। लेकिन, अगर सगाई टूट जाती है तो क्या होता है? दशकों पुराने उस कानून को पलटते हुए, जिसमें कहा गया था कि सगाई टूटने के लिए जिम्मेदार साथी को अंगूठी नहीं मिलनी चाहिए, मैसाचुसेट्स की एक अदालत ने हाल ही में आदेश दिया कि सगाई की अंगूठी खरीदार को वापस करनी होगी, चाहे अलगाव के पीछे कोई भी हो। शायद यह आखिरकार रिश्ते में प्यार और प्रतिबद्धता को व्यक्त करने के विचार को महंगी अंगूठी के तोहफे से अलग कर देगा। उत्तर प्रदेश के संभल क्षेत्र में जामा मस्जिद के न्यायालय द्वारा नियुक्त सर्वेक्षण का विरोध कर रही भीड़ की सुरक्षाकर्मियों से झड़प में कम से कम चार लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। सर्वेक्षण आयोग के साथ आए कुछ लोगों ने प्रदर्शनकारियों को भड़काने के लिए जय श्री राम का नारा लगाया और स्थानीय पुलिस ने सख्ती से काम किया। इसके अलावा, दंगाइयों के पास चाकू और पिस्तौल थे, जिन्हें रोकने में पुलिस विफल रही। इससे पता चलता है कि हिंसा सुनियोजित थी (श्भड़काऊश नारे और पुलिस की भूमिका पर संभल की नजर, 26 नवंबर)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भय फैलाने और नफरत फैलाने वाले भाषणों ने राज्य में माहौल खराब कर दिया है। काजीपेट, तेलंगाना महोदय कृ हाल ही में एक सिविल कोर्ट ने संभल में जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया है। यह उन याचिकाओं पर आधारित है, जिनमें दावा किया गया है कि मुगल बादशाह बाबर ने 1529 में हरिहर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई थी। इससे पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के क्रियान्वयन को लेकर चिंताएं पैदा होती हैं, जिसमें पूजा स्थलों के धार्मिक चरित्र को वैसा ही बनाए रखने का आदेश दिया गया है जैसा कि 15 अगस्त, 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिलने के समय था। रामजन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ऐसी याचिकाएं आम हो गई हैं और इससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट को पूजा स्थलों के धार्मिक चरित्र में बदलाव को रोकना चाहिए और धर्मनिरपेक्षता के संवैधानिक सिद्धांत को कायम रखना चाहिए। अंशु भारती, बेगूसराय, बिहार महोदय – संभल में हुई हिंसा के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की मनमानी जिम्मेदार है, जिसने दंगाइयों को खुली छूट दे दी। इस तरह की हिंसा को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। मुर्तजा अहमद, कलकत्ता महोदय – संभल मस्जिद में हाल ही में हुई हिंसा के कारण भारत का सांप्रदायिक सद्भाव का दावा सवालों के घेरे में आ गया है। ऐसी घटनाएं सामाजिक एकता को खतरे में डालती हैं। राजनेताओं को गलत सूचनाओं से निपटने और अपराधियों को जिम्मेदार ठहराने की जरूरत है। शयाक मोइन, मुजफ्फरपुर महोदय कृ संभल में एक मस्जिद पर विवाद 2022 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का नतीजा है, जिसमें कहा गया है कि "धार्मिक स्थल की प्रकृति का पता लगाना" 1991 के कानून के तहत प्रतिबंधित नहीं है। मस्जिदों को निशाना बनाना और उन्हें कथित तौर पर मुगल सम्राटों द्वारा ध्वस्त किए गए पुराने हिंदू मंदिर होने का दावा करना मुसलमानों को डराने के लिए भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आजमाई हुई रणनीति है। दुर्भाग्य से, कानून प्रवर्तन और न्यायपालिका ने अल्पसंख्यक समुदाय की पीड़ाओं पर आंखें मूंद ली हैं। जरूरी अयमान अनवर अली, कलकत्ता असफल प्रयास महोदय कृ बाकू, अजरबैजान में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के दलों का 29वां सम्मेलन निराशाजनक रहा यह न केवल वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को बढ़ावा देने में विफल रहा, बल्कि विकासशील देशों की अपेक्षाओं को भी पूरा करने में विफल रहा, जो महामारी और चल रहे युद्धों के कारण आर्थिक मंदी से उभरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सीओपी 29 कैसे विकसित देशों और विकासशील देशों को बराबरी पर रख सकता है और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए कठोर कदम उठाने की बात आने पर

विकासशील देशों से भारी काम करने की उम्मीद कर सकता है? जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कुख्यात डोनाल्ड ट्रम्प के संयुक्त राज्य अमेरिका में सत्ता में वापस आने के साथ, जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक प्रयास और भी पटरी से उतर जाएंगे। बाल गोविंद, नोएडा महोदय कृ श्जलवायु वित्त सीओपीश के रूप में बिल किया गया, हाल ही में बाकू में आयोजित सम्मेलन एक समझौते को अपनाने के साथ संपन्न हुआ, जो विकासशील देशों को 2035 तक सालाना 300 बिलियन डॉलर की जलवायु सहायता प्रदान करेगा। यह विकासशील देशों द्वारा वैश्विक तापमान वृद्धि को रोकने के लिए आवश्यक 1.3 ट्रिलियन डॉलर से बहुत कम है। निराशाजनक रूप से, 2009 म 15 में निर्धारित 2020 तक +100 बिलियन का वित्तपोषण करने का लक्ष्य विकसित देशों को पूरा करने में बहुत लंबा समय लगा। 2035 तक वादा किया गया +300 बिलियन का अनुदान अधिक निवेश आकर्षित करने और जलवायु वित्त को +1.3 ट्रिलियन के आंकड़े की ओर ले जाने के लिए एक बीज निधि हो सकता है, लेकिन यह राशि ज्यादातर ऋण के रूप में आएगी, जिससे विकासशील देश अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे। विकासशील देशों पर असंगत बोझ डालना जी के लिए अच्छा नहीं है।

कनाडा एवं अमेरिका से भारत में रिवर्स ब्रेन ड्रेन की सम्भावना बढ़ रही है

प्रह्लाद सबनानी

वैश्विक स्तर पर लगातार कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित होती दिखाई दे रही हैं, जिससे विशेष रूप से कनाडा एवं अमेरिका से भारत की ओर रिवर्स ब्रेन ड्रेन की सम्भावना बढ़ती जा रही है। कनाडा में खालिस्तानियों द्वारा चलाए जा रहे भारत विरोधी आंदोलन के चलते वहां निवासरत भारतीयों एवं मंदिरों पर लगातार हमले हो रहे हैं एवं भारतीयों एवं मंदिरों पर हो रहे इन हमलों पर लगाम लगाने में कनाडा की वर्तमान सरकार असफल सिद्ध हो रही है एवं इन हमलों को, राजनैतिक कारणों के चलते, रोकने की इच्छा शक्ति का अभाव भी दिखाई दे रहा है। इसके चलते भारत एवं कनाडा के राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक रिश्तों पर अत्यधिक विपरीत प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। स्थिति तो यहां तक पहुंच गई है कि भारत ने कनाडा में अपने दूतावास में प्रतिनिधियों की संख्या को कम कर दिया है तथा भारत ने कनाडा को निर्देशित किया था कि वह भी भारत में अपने दूतावास में प्रतिनिधियों की संख्या को कम करे। भारत एवं कनाडा के बीच आज कूटनीतिक रिश्ते आज तक के सबसे निचले स्तर पर आ गए हैं। साथ ही, कनाडा में आज सुरक्षा की दृष्टि से भी स्थितियां तेजी से बदल रही हैं तथा इसका कनाडा के आर्थिक विकास पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिसके चलते भारतीय आज कनाडा में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और भारत की ओर रुख कर रहे हैं। दूसरी ओर, अमेरिका में डोनल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के पश्चात वहां पर अवैध रूप से रह रहे अन्य देशों के नागरिकों को अमेरिका से निकाले जाने की सम्भावनाएं बढ़ गई हैं। हालांकि अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों की संख्या लगभग नगण्य सी ही है परंतु ट्रम्प प्रशासन द्वारा अब वीजा, एच1बी सहित, जारी करने वाले नियमों को और अधिक कठोर बनाया जा सकता है। अमेरिका में प्रतिवर्ष जारी किए जाने वाले कुल एच1बी वीजा में से 60 प्रतिशत से अधिक वीजा भारतीय मूल के नागरिकों को जारी किए जाते हैं। यदि इस संख्या में भारी कमी दृष्टिगोचर होती है तो अमेरिका में पढ़ रहे भारतीय छात्रों को, उनकी पढ़ाई सम्पन्न करने के पश्चात यदि एच1बी वीजा जारी नहीं होता है तो उन्हें भारत वापिस आने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इस प्रकार अमेरिका से भी भारतीयों का रिवर्स ब्रेन ड्रेन दिखाई पड़ सकता है। भारत आज पूरे विश्व में सबसे अधिक तेज गति से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया है, अतः भारत में तेज गति से हो रहे आर्थिक विकास के कारण सूचना प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, उच्च तकनीकी क्षेत्रों, वाहन विनिर्माण उद्योग, फार्मा उद्योग, चिप विनिर्माण उद्योग, स्टार्ट अप, आदि क्षेत्रों में भारी मात्रा में रोजगार के नए अवसर निर्मित हो रहे हैं और भारत को इन क्षेत्रों में उच्च टेलेंट की आवश्यकता भी है। यदि कनाडा एवं अमेरिका से उच्च शिक्षा प्राप्त एवं उक्त क्षेत्रों में प्रशिक्षित इंजीनीयर्स भारत को प्राप्त होते हैं तो यह स्थिति भारत के लिए बहुत फायदेमंद होने जा रही है। उक्त कारणों के अतिरिक्त आज अन्य देशों से भारत की ओर रिवर्स ब्रेन ड्रेन इसलिए भी होता दिखाई दे रहा है क्योंकि, भारत में आज मूलभूत सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। किसी भी दृष्टि से भारत का आधारभूत ढांचा आज किसी भी विकसित देश की तुलना में कम नहीं है। साथ ही, भारत में, विकसित देशों की तुलना में, मुद्रा स्फीति की दर कम होने से, सामान्य रहन सहन की लागत तुलनात्मक रूप से भारत में बहुत कम है। अतः भारत में अमेरिका एवं कनाडा की तुलना में शुद्ध बचत दर भी अधिक है। हाल ही के समय में भारत में स्वास्थ्य सेवाओं में भी पर्याप्त सुधार हुआ है। आज बैंगलोर, मुंबई, हैदराबाद जैसे शहरों में बहुत ही कम लागत पर अमेरिकी अस्पतालों की तुलना में (अमेरिका की तुलना में तो 1ध्10 लागत पर) अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं। भारत के ग्रामीण इलाकों में तो शुद्ध हवा एवं शुद्ध पानी, जो स्वास्थ्य को ठीक बनाए रखने में सहायक होता है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। वरना, महानगरीय इलाकों में तो आज सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। विभिन्न देशों से उच्च शिक्षा प्राप्त एवं टेलेंटेड भारतीय जो भारत वापिस लौटे हैं, उन्होंने अपने नए प्रारम्भ किए गए स्टार्ट अप के कार्यालय दक्षिण भारत के ग्रामीण इलाकों में स्थापित किए हैं। भारत में बहुत लम्बे समय से मजबूत लोकतंत्र बना हुआ है एवं केंद्र में एक मजबूत सरकार, उद्योग एवं व्यापार को भारत में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उद्योग एवं व्यापार के मित्रवत आर्थिक

नीतियों को सफलतापूर्वक लागू कर रही है। इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मात्रा में अपार वृद्धि दृष्टिगोचर हुई है। विकसित देशों में नागरिकों की औसत आयु 50 वर्ष से अधिक हो रही है जिससे श्रमिकों की संख्या इन देशों में लगातार कम हो रही है एवं श्रम लागत में भी भारी मात्रा में वृद्धि हुई है जिसके कारण इन देशों में उत्पादन लागत बहुत अधिक बढ़ गई है। हाल ही के समय में चीन भी इस समस्या से ग्रसित पाया जा रहा है। केवल भारत एवं दक्षिणी अफ्रीकी देशों में ही श्रम लागत तुलनात्मक रूप से बहुत कम है। इसके कारण विश्व की कई बहुराष्ट्रीय कम्पनियां अपनी विनिर्माण इकाईयों की स्थापना भारत में करना चाहते हैं। भारत में उत्पादों का निर्माण कर इन उत्पादों को विश्व के अन्य देशों को निर्यात किया जा रहा है। भारत में आटोमोबाईल उद्योग, मोबाइल उद्योग एवं फार्मा उद्योग इसके जीते जागते प्रमाण हैं। इन्हीं कारणों से आज भारत से कई उत्पादों का निर्यात बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है एवं भारत का विदेशी व्यापार घाटा लगातार कम हो रहा है। विदेशी व्यापार घाटे में सुधार होने के चलते भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में भी वृद्धि दृष्टिगोचर है जो हाल ही के समय में 70,000 अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को भी पार कर गया था। हालांकि, इसके बाद से इसमें कुछ गिरावट देखी गई है। आज विश्व के कई विकसित देशों में सामाजिक तानाबाना छिन्न भिन्न हो गया है एवं इन देशों के नागरिकों में मानसिक असंतोष की भावना लगातार बढ़ रही है एवं इन देशों की आधे से अधिक आबादी आज मानसिक बीमारियों से ग्रसित है। जबकि इसके ठीक विपरीत भारत में हिंदू सनातन संस्कृति के संस्कारों के अनुपालन से एवं संयुक्त परिवार की जीवनशैली के चलते भारतीय नागरिक मानसिक बीमारियों से लगभग पूर्णतरू मुक्त रहे हैं एवं सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। विकसित देशों के नागरिकों ने भौतिक विकास तो अधिक किया है परंतु मानसिक शांति खोई है। जबकि इस धरा पर जन्म लेने का उद्देश्य ही सुखी जीवन व्यतीत करना है न कि अपने आप को मानसिक बीमारियों से ग्रसित कर देना। इन्हीं कारणों के चलते आज विश्व के कई देशों के नागरिक हिंदू सनातन संस्कृति को अपनाने की ओर लालायित दिखाई दे रहे हैं और वे भारत में बसने के बारे में गम्भीरता से विचार कर रहे हैं। अतः विकसित देशों से भारत में रिवर्स ब्रेन ड्रेन आने वाले कल की सच्चाई है।

उच्च न्यायपालिका के द्वारा कानून के शासन और संवैधानिक मूल्यों को कायम रखना

सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा कानून, 2004 की संवैधानिक वैधता बरकध्रार रखी है। साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला खधरिज कर दिया है। उत्तर प्रदेश में मदरसों (इस्लामिक शैक्षणिक

संस्थानों) के कामकाज को विनियमित और नियंत्रित करने के उद्देश्य से श्उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004श लागू किया गया था। इसने पूरे उत्तर प्रदेश में मदरसों की स्थापना, मान्यता, पाठ्यक्रम और प्रशासन के लिये एक ढाचा प्रदान किया। इस अधिनियम के तहत, राज्य में मदरसों की गतिविधियों की देखरेख और पर्यवेक्षण के लिये उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई थी। टकराने से सडक पर गिरी टहनियां मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए श्कहा कि सरकार मदरसा शिक्षा को लेकर नियम बना सकती है। यह फैसला भारतीय मुसलमानों और मदरसों से जुड़े लोगों के लिए संतोषजनक और प्रेरणादायक है। इस निर्णय से देश में न्याय और समानता का संदेश गया है। अदालत ने कहा की मदरसा एक्ट के प्रावधान संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप हैं और ये श्धार्मिक अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। जब धार्मिक शिक्षा और अल्पसंख्यकों के शिक्षा के अधिकार की बात आती हे तो हम पाते है कि संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक समुदायों को अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उन्हें स्वतंत्र रूप से संचालित करने श्का अधिकार दिया है। काम पूरा न होने से लोग परेशान भारतीय संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, और इसके प्रावधान सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। इन संवैधानिक अधिकारों को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर इस बात पर प्रकाश डाला हे कि कोई भी कानून, विनियमन या सामाजिक पूवाग्रह संविधान के प्रावधानों को खत्म नहीं कर सकता है। यह निर्णय उस कानूनी ढांचे को मजबूत करता है जिसके भीतर अल्पसंख्यक समुदाय काम कर सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनहें ऐसे संस्थान बनाने की स्वतंत्रता है जो उनकी अद्वितीय शैक्षिक आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करते हैं। संविधान की सर्वोच्चता ही भारत के लोकतंत्र श्को स्थिरता और सुसंगति प्रदान करती है। ऐसे देश में जहां कई धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक समुदाय सह अस्तित्व में हैं, संविधान एक एकीकृत दस्तावेज क रूप में कार्य करता हैजो समानता सुनिश्चित करते हुए विविधता की रक्षा करता है। यह निर्णय इस बात की पुष्टि करता है कि न्यायपालिका, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक के रूप में, इसके प्रावधानों से किसी भी विचलन की अनुमति नहीं देगी। ऐसा करके न्यायालय ने स्पष्ट संदेश दिया है कि संवैधानिक अधिकारों को कमजोर या समझोता नहीं किया जा सकता है। यह निर्णय यह भी दर्शाता है कि कैसे संविधान को समुदायों को अपने भविष्य को आकार देने के लिए सशक्त श्बनाने के लिए बनाया किया गया है। संविधान केवल अधिकारों की रक्षा नहीं करता, यह सामाजिक और शैक्षणिक उन्नति के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करके राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी को श्प्रोत्साहित करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के माध्यम से, इन अधिकारों की पुष्टि श्करके अल्पसंख्यक समुदायों को प्रभावी ढंग से सशक्त बनाया है,। इस प्रकार सामाजिक प्रगति और न्याय के एक शक्तिशाली साधन के रूप में संविधान की भूमिका को मजबूत किया है।

पढ़ने के साथ समझना भी जरूरी

हमारे यहां श्शब्दश को ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म यानी कि इस संसार की रचना करने वाला। तो क्या शब्द भी ब्रह्म की तरह दुनिया का निर्माण करते हैं? आइए, इसे एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। मान लीजिए, आप आराम से चुपचाप बैठे हुए हैं। कोई अचानक आकर ही आपको गालियां देने लगता है। अभी तक आप शांत थे। गालियां सुनने के बाद आपको गुस्सा आ गया। अब आपके अंदर की दुनिया क्या पहली जैसी ही शांत है? नहीं न वह बदल गई है और इस दुनिया को बनाने का काम मात्र कुछ शब्दों ने ही तो किया है। इससे यह सिद्ध होता है कि हम जो भी सुनते और बोलते हैं, उनका बहुत गहरा और सीधा संबंध हमारे विचारों और हमारी भावनाओं से होता है। और मैं आपसे पूछूं कि आप फिलहाल कौन सा काम कर रहे हैं, तो आपका उत्तर होगा मैं पढ़ाई कर रहा हूं। हर छात्र और उनके माता–पिता इस काम को श्पढाई करनाश ही कहते हैं। लेकिन आपके लिए मेरी चिंता यह है कि आप श्पढ़ाई कर रहे हैं या आप अध्ययन कर रहे हैं। आप जब अपने कोर्स की किताबों के साथ होते हैं, तब आप उसे पढ़ रहे होते हैं, या उसकी स्टडी कर रहे होते हैं? आपके इस उत्तर से आपके अंतर्मन की स्थिति जुड़ी हुई है। जैसे कोई व्यक्ति उपन्यास पढ़ रहा है, लेकिन जब उसी उपन्यास को हिंदी साहित्य का विद्यार्थी अपने सिलेबस के कारण पढ़ता है, तो इन दोनों के पढ़ने के तरीके में बहुत द्य अंतर आ जाएगा। वह व्यक्ति उस उपन्यास को मनोरंजन के लिए पढ़ रहा है। उसे न तो उपन्यास की घटनाओं को याद रखने की जरूरत है और न ही उसे उसकी समीक्षा करनी है। लेकिन हिंदी साहित्य के विद्यार्थी को उस उपन्यास के प्रति गंभीर होकर ध्यान से पढ़ना होगा और उसे समझना भी होगा। इसी तरह जब आप अपनी पढ़ाई गंभीर होकर करने लगते हैं, तब वह पढ़ाई अपने आप ही अध्ययन बन जाती है। बदलाव इसलिए मेरे इस लेख का आपके लिए मूल सूत्र यह है कि आप अपने दिमाग मैं इस वाक्य को बैठा लें कि श्मैं पढ़ाई नहीं अध्ययन कर रहा हूं।श आपका यह वाक्य आपके अंदर एक ऐसी दुनिया की रचना कर देगा, जिसकी ग्रहण करने की क्षमता पहले की तुलना में कई गुना बढ़ जाएगी। इससे स्मरण शक्ति में भी इजाफा हो जाएगा। पढ़ाई को बोझ न समझेंरू जब हम पढ़ने को अध्ययन में तब्दील कर देते हैं, ।

विद्यास्थली ने मचाया डबल धमाल

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। वाराणसी में आयोजित 4TH रग्बी ओपन चौम्पियनशिप में विद्यास्थली के छात्र तथा छात्राओं ने क्रमशरू प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करके डबल धमाल मचा दिया। यह चौंपियनशिप रग्बी संगठन द्वारा

वाराणसी में 27 नवंबर को आयोजित की गई थी। विद्यास्थली की प्रधानाचार्या श्रीमती शिप्रा वर्मा ने बच्चों के साहस, लगन तथा अच्छे प्रदर्शन की जमकर प्रशंसा की तथा उज्जवल भविष्य हेतु बच्चों को शुभाशीष प्रदान किया है।

आईएमएस, लखनऊविश्वविद्यालय ने 29.11.24 को डिकोडिंग पर्सनल एंड प्रोफेशनल सक्सेस पर विशेष व्याख्यान का आयोजन किया

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज (आईएमएस) ने ष्डिकोडिंग पर्सनल एंड प्रोफेशनल सक्सेसष् पर विशेष व्याख्यान का आयोजन किया। विशेष व्याख्यान का आयोजन लखनऊ विश्वविद्यालय के सम्मानित कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय एवं सम्मानित प्रोफेसर. विनीता काचर, ओएसडी, प्रबंधन विज्ञान संस्थान, लखनऊ विश्वविद्यालय के मार्गदर्शन में किया गया। जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, लखनऊ, नोएडा, जयपुर, इंदौर परिसर के सलाहकार और प्रतिष्ठित प्रोफेसर डॉ. वीरेंद्र पी सिंह आईएमएस के सेमिनार हॉल में मुख्य वक्ता थे। कार्यक्रम की शुरूआत दीप प्रज्वलन से हुई। डॉ. अमिताभ रॉय ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और मोमेंटो भेंट किया। उन्होंने जीवन में सफलता और महत्व, सफल लोगों के लिए स्टीफन कोवी की सात आदतों, जीने, सीखने, प्यार करने, विरासत छोड़ने की अवधारणा, कॉर्पोरेट जगत क्या चाहता है, जोहारी विंडोस ने जीवन में व्यावहारिकताएं और लक्ष्य निर्धारण के बारे में बताया। कार्यक्रम में आईएमएस के संकाय सदस्यों और लखनऊ विश्वविद्यालय के नए परिसर में प्रबंधन के छात्रों ने भाग लिया। छात्रों को विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षित किया गया। छात्र अत्यधिक प्रेरित थे।

महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा सम्मान एवं स्वावलंबन हेतु मिशन शक्ति : संतोष कुशवाहा

हरदोई (अम्बरीष कुमार सक्सेना) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई के अध्यक्षध्जनपद न्यायाधीश माननीय संजीव शुक्ला तथा सचिवध्अपर जिला जज माननीय भूपेंद्र प्रताप के आदेशानुसार, तहसील विधिक सेवा समिति शाहाबाद सचिवध्तहसीलदार अजय कुमार के दिशानिर्देशन तथा नायब तहसीलदार संतोष कुशवाहा की अध्यक्षता में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा सम्मान एवं स्वावलंबन हेतु मिशन शक्ति विशेष अभियान के पांचवें चरण के संचालन हेतु विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन कस्तूरवा गांधी बिलहरी, में किया गया। जिसमें श्री संतोष कुशवाहा द्वारा बताया गया महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने मिशन शक्ति नाम की योजना शुरू की है इस योजना का मकसद महिलाओं और बालिकाओं को अल्प और दीर्घकालिक सेवाएं देकर उनकी देखभाल सुरक्षा और विकास करना है महिलाओं के अधिकार तथा योजनाओं के विषय में जानकारी दी। कस्तूरवा गांधी विद्यालय की प्रधान्याचार्य सुश्री अशोक कुमारी ने बालिकाओं के अधिकारों की जानकारी दी

तथा नामिका अधिकवक्ता श्री आशुतोष त्रिपाठी ने बताया कि बालिकाओं के अधिकार मानव अधिकार हैं महिलाओं और बालिकाओं को भी वही मौलिक अधिकार मिलनी चाहिए जो पुरुषों को मिलते हैं इन अधिकारों में शामिल है शिक्षित होने का अधिकार ,संपत्ति का मालिक होने का अधिकार समान वेतन पाने का अधिकार तथा अन्य अधिकारों के विषय में जानकारी दी। श्री मोहम्मद शाजेब सिद्दीकी ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाई जा रही निशुल्क विधिक सेवाएं एवं हेल्पलाइन नंबर 15100 की जानकारी दी। शिविर में पी एल वी सुशील कुमार, शिक्षकगण एवं छात्राएं आदि उपस्थित रहे।

नहीं रहे रामलीला के उत्कृष्ट कलाकार एडवोकेट दीपेश त्रिपाठी

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। आज श्री राम लीला समिति महानगर से जुड़े उत्कृष्ट कलाकार 49 वर्षीय एडवोकेट दीपेश त्रिपाठी का लम्बी बीमारी के बाद निध न हो गया। बचपन से रामलीला में विभिन्न पात्रों का अभिनय करते हुए रामलीला मंचन की व्यवस्था सम्हालते थे। उन्होंने श्री रामलीला समिति में सांस्कृतिक सचिव और महासचिव भी पद संभाल। उन्हें गोस्वामी तुलसीदास सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका। दीपेश त्रिपाठी के परिवार में उनके वयोवृद्ध पिता क्षेम चन्द्र त्रिपाठी, माता श्रीमती भगवती त्रिपाठी, पत्नी नीलिमा त्रिपाठी, भाई मेजर सोमेश त्रिपाठी और बहन नैनीताल उच्च न्यायालय की अधि वक्ता सुश्री मेनका त्रिपाठी हैं। आज प्रातः दस बजे उनकी अन्तिम यात्रा महानगर स्थित आवास से प्रारंभ होकर बैकुंठ धाम पहुंची उनकी अंतिम यात्रा में रामलीला समिति के अध्यक्ष ललित मोहन जोशी महासचिव हेम पन्त उपाध्यक्ष विनोद पन्त कोषाध्यक्ष नीरद लोहानी रामलीला के निदेशक महेंद्र पन्त सह निर्देशक हरीश लोहुमी मुख्य संयोजक गिरीश जोशी संयोजक दीपक पांडे दीनू रामलीला समिति के पदाधिकारी संजय पांडे हिमांशु मिश्रा आनंद सिंह दीपेश पांडे नवीन पांडे नीरज पन्त नलिन पन्त बृजेश मेहता बलवंत देवड़ी जयप्रकाश उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ बेंच की अधिवक्ता पुष्पीला बिष्ट लाबीर सिंह बिष्ट सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे।

प्रदेश स्तरीय समन्वय सब जूनियर बालिका हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन 16 से 21 दिसम्बर,तक इटावां में : अतुल सिन्हा

ब्यूरो प्रमुख

विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। खेल निदेशालय उ0प्र0, लखनऊ के तत्वावधान में खेल विभाग उ0प्र0 एवं उ0प्र0 हॉकी संघ के समन्वय से प्रदेश स्तरीय समन्वय सब जूनियर बालिका हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन 16 से 21 दिसम्बर, तक इटावां में किया जा रहा है। इस संबंध में शुक्रवार को देश की उपासना समाचार पत्र के ब्यूरो प्रमुख बात करते हुए जिला क्रीड़ा अधिकारी अतुल कुमार सिन्हा ने बताया कि उक्त के क्रम में जनपद जौनपुर के सब जूनियर बालिका हॉकी खिलाड़ियों का जनपदीय चयन परीक्षण 4 दिसम्बर को सुबह 10 बजे से इन्दिरा गांधी स्टेडियम सिद्दीकपुर में किया जायेगा। जनपद स्तर पर चयनित सब जूनियर हॉकी खिलाड़ी ही दिनांक 06 दिसम्बर, 2024 को आयोजित मण्डल स्तरीय चयनध्ट्रायल्स, डॉ0 भीमराव अम्बेडकर क्रीड़ा संकुल लालपुर, वाराणसी में प्रातः 9.30 बजे से किया जायेगा, में प्रतिभाग करेंगी। मण्डल स्तरीय चयनध्ट्रायल्स उपरान्त मण्डल की टीम का गठन किया जायेगा, मण्डल स्तरीय टीम ही प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता जो इटावां में आयोजित हो रही है, में प्रतिभाग करेगी। इच्छुक खिलाड़ी निर्धारित प्रारूप पर अपना पात्रता प्रमाण पत्र फोटो सहित तथा आयु प्रमाण–पत्र प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित तथा आधार कार्ड के साथ, हाई स्कूल अंक पत्र की छायाप्रति साथ लेकर जनपदीय चयनध्परीक्षण में प्रतिभाग कर सकते हैं।

भाजपा सरकार में बनी हर सड़क में भ्रष्टाचार है : सपा नेता राजपाल कश्यप

हरदोई(अम्बरीष कुमार सक्सेना) हरदोई जिले में बनी सड़कों के निर्माण में घोटाले पर बोलते हुए सपा नेता और पूर्व विधायक राजपाल कश्यप ने कहा कि भाजपा सरकार में बनी हर सड़क में भ्रष्टाचार है। अगर सभी सड़कों की जांच कर ली जाए तो महा घोटाला उजागर हो जाएगा। प्रदेश सरकार ने हरदोई जिले में लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई सड़कों में घोटाला पाया है। जिस पर मुख्यमंत्री ने 28 नवंबर को 16 अभियंताओं को निलंबित भी कर दिया। इस घोटाले को लेकर पूर्व एमएलसी और सपा नेता राजपाल कश्यप ने कहा कि भाजपा सरकार घोटाले की सरकार है। जिस बुंदेलखंड एक्सप्रेस का प्रधानमंत्री ने लोकार्पण किया वह अगले दिन ही धस गई, पूरे देश प्रदेश के अधिकारियों में देख रेख

में बनी अयोध्या की सड़के पहली बरसात ही सड़के झेल नहीं पाई। डॉ. कश्यप ने कहा और तो और देश की सर्वोच्च संस्था के मंदिर संसद भवन में भी पानी टपकना घोटाले को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह सब अधिकारियों के स्तर से नहीं बल्कि सरकार के स्तर से भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर सभी सड़कों की जांच कर ली जाए तो महा घोटाला उजागर होगा डॉ. कश्यप ने कहा कि अखिलेश यादव द्वारा बनवाए गए आगरा एक्सप्रेसवे का कई बार भाजपा सरकार ने परीक्षण कराया लेकिन कहीं पर भी कोई कमी नहीं पाई गई।

शांतिपूर्वक मस्जिदों में अदा की गई जुम्मे की नमाज पुलिस प्रशासन रहा चौकन्ना

क्षेत्राधिकार शहर देवेश कुमार सिंह शहर कोतवाल मिथिलेश कुमार मिश्रा लगातार करते रहे मस्जिदों का चक्रमण

ब्यूरो प्रमुख

विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,। यूपी के संभल में मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा को लेकर जहां पूरा प्रदेश का पुलिस महकमा अलर्ट मोड पर है तो वही जनपद जौनपुर में शुक्रवार को जुम्मे की नमाज शांतिपूर्वक अदा किया जाए इसको लेकर बात करें तो नगर के अटाला मस्जिद शाही ईदगाह , बड़ी मस्जिद व अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में भी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। शुक्रवार दोपहर 1रू00 बजे शुरू हुई नमाज सकुशल संपन्न होने के उपरांत पुलिस वापस गई

।इस दौरान शांति व्यवस्था बनी रहे इसको लेकर शहर कोतवाल मिथिलेश मिश्र संबंधित स्थान की पुलिस चौकियों के इंचार्ज व क्षेत्राधिकार सदर देवेश कुमार सिंह लगातार मस्जिदों का चक्रम करते रहे। शुक्रवार को बड़ी मस्जिद व अटाला मस्जिद नगर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक पुलिस मुस्तैद रही।दोपहर 1 बजे शहर के बड़ी मस्जिद में मुस्लिम समुदाय के द्वारा नमाज अदा किया गया ।वही पर शहर कोतवाल मिथिलेश मिश्रा ने बताया कि जुमे की नमाज को सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतेजाम किये गए है। इस संबंध में बात करते हुए सीओ सिटी देवेश कुमार सिंह ने बताया कि जुमे की नमाज में काफी भीड़ होती है, हर जुमे की नमाज को पुलिस की तरफ से सतर्कता बरती जाती है आज भी इसी रूटीन में चक्रमण किया जा रहा है । हालांकि जनपद की गंगा जमुना तहजीब को लेकर शांति व्यवस्था हमेशा कायम रही है आज भी जुम्मे की नमाज शांतिपूर्वक अदा की गई । यहां संभल जैसी किसी लड़की कोई घटना नहीं है पूरे जिले में शांतिपूर्वक नमाज अदा किया गया है।

पुलिस ने कार से कुचल कर हत्या करने वाले तीन नामजद वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार

घटना मे प्रयुक्त स्वीफ्ट कार बरामद

ब्यूरो प्रमुख

विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर ,29 नवंबर । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ0 अजय पाल द्वारा अपराधियों एवं वांछित अपराधि ायों की गिरफ्तारी के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के अरविंद कुमार वर्मा क्षेत्राधिकारी केराकत घनानन्द त्रिपाठी प्रभारी निरीक्षक जलालपुर मय हमराह पुलिस टीम के क्षेत्र मे भ्रमण कर रहे थे इस दौरान नामजदध्वांछित अभियुक्तगण अभिषेक सिंह पुत्र दिनेश सिंह ,रोहित कुमार सिंह पुत्र नरसिंह बहादुर नि0गण ग्राम रेहटी थाना जलालपुर जौनपुर ,अविनाश सिंह पुत्र अशोक सिंह नि0ग्राम लोहगाजर जलालपुर को मुखबिर की सूचना के आधार पर कस्बा जलालपुर से गिरफ्तार कर हिरासत मे लिया गया। घटना में प्रयुक्त कार स्वीफ्ट यू0पी0 62 सी0यू0 2777(काला रंग) की बरामद की गयी बरामदगी व गिरफ्तारी नियमानुसार अग्रिम विधि ाक कार्यवाही की जा रही है।विदित हो कि जनपद के जलालपुर थाना क्षेत्र के मकरा चौराहे पर बुधवार को दबंगों ने मामूली विवाद को लेकर एक युवक पर गाड़ी चढा कर हत्या कर दी है। हत्या से गांव भर में कोहराम मच गया। मालूम हो कि रेहटी गांव निवासी पंकज

राजभर (24) का उसी गांव निवासी छोटू सिंह और रोहित सिंह का किसी बात को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि गुस्साए छोटू सिंह और रोहित सिंह ने अपनी कार पकंज राजभर के उपर चढा दिया। इतना ही नहीं दोनों ने उस पर कार चढाकर आगे पीछे करते हुए कई बार कुचला जिससे पंकज गंभीर रूप से घायल होकर अचेत हो गया। घटना के बाद परिजनों युवक को वाराणसी ले गएं जहां डॉक्टरों ने देखते ही उसे मृत घोषित कर दिया था।

खेल कूद से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है : आशुतोष सिन्हा

ब्यूरो प्रमुख

विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर नगर स्थित बीआरपी इन्टर कॉलेज में वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में शुक्रवार से शनिवार तक को वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता आयोजन बी आर पी इंटर कॉलेज में किया गया है। शुक्रवार को उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष मनोरमा मौर्या एवं मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य आशुतोष सिन्हा रहे। अध्यक्ष मनोरमा मौर्या ने बच्चों को अपना आशीर्वाद देते हुए कहा कि इस तरह की प्रतियोगिता बच्चों के अंदर अपनी प्रतिभा दिखाने का सशक्त माध्यम होती है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आशुतोष सिन्हा ने खेलकूद और शिक्षा के सम्बन्ध के बारे में बताया कहा कि खेल कूद से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। इस तरह के कार्यक्रम स्कूलों में आयोजित होने से बच्चों के अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना को बल मिलता है इस तरह के कार्यक्रम समय–समय पर कॉलेज में आयोजित किए जाने चाहिए। उन्होंने कॉलेज के विकाश के लिए अपने निधि से 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया। इस मौके पर स्कूल के प्रबंधक हरिशचन्द्र श्रीवास्तव ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपना आशीर्वाद दिया। विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह दे कर सबका सम्मान किया। विभिन्न प्रतिस्पर्धा में जैसे 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर की दौड़ में अर्जुन कश्यप, ज्योति श्रीवास्तव, आँचल सोनकर और आफान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम का संचालन डॉ विमल श्रीवास्तव ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रविन्द्र अस्थाना (अध्यक्ष बी आर पी प्रबंध समिति), दिलीप श्रीवास्तव (प्रबंधक) मुक्तेश्वर प्रसाद बालिका इन्टर कॉलेज, अंशु श्रीवास्तव एवं राजन श्रीवास्तव उपस्थित रहे। जंग बहादुर सिंह (प्रधानाचार्य दृ जनक कुमारी इन्टर कॉलेज), डा संजय चौबे (प्रध ानाचार्य दृ राज कॉलेज), कंचन जस्मिन ल्युक (प्रधानाचार्य – मुक्तेश्वर बालिका इन्टर कॉलेज), प्रदीप श्रीवास्तव (विकास अधि कारी), सुशील श्रीवास्तव (जिला प्रतिनिधि),राजेश श्रीवास्तव पत्रकार , विश्वप्रकाश श्रीवास्तव पत्रकार विनोद विश्वकर्मा पत्रकार , आदि उपस्थित रहे। खेल कूद का सफल संचालन प्रकाश यादव एवं रविन्द्र यादव ने किया, कार्यक्रम में सभी शिक्षक एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे। कल भी प्रतियोगिता जारी रहेगी। उक्त जानकारी मीडिया प्रभारी दीपक श्रीवास्तव ने दिया।

आगरा विवि ने लगाई नकल पर लगाम, चार कॉलेजों पर 50-50 हजार का जुर्माना

आगरा,(संवाददाता)। डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षा में परीक्षा केंद्रों में जमकर नकल कराई जा रही है। परीक्षा शुरू होने के एक सप्ताह बाद भी फिरोजाबाद के तीन और मथुरा के एक केंद्र ने सीसीटीवी कैमरा विश्वविद्यालय के नियंत्रण कक्ष से लिंक नहीं करवाए हैं। अब इन केंद्रों पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने 50–50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही दो दिन के भीतर कैमरा लिंक कराने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद भी कॉलेजों ने सीसीटीवी कैमरा लिंक नही करवाए तो इनके केंद्र निरस्त कर दिए जाएंगे। डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय की विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं 21 नवंबर से शुरू हुई हैं। परीक्षा की निगरानी के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी परीक्षा केंद्रों को विश्वविद्यालय के खंदारी परिसर में बने नियंत्रण कक्ष से जोड़ा है। यहां जिलेवार कर्मचारियों की तैनाती की गई है, जो परीक्षा के दौरान संबंधित जिले की परीक्षा की निगरानी करते हैं। परीक्षा के दौरान कई केंद्रों के सीसीटीवी कैमरा बंद नजर आते हैं। बार–बार संपर्क करने पर तकनीकी खामी का हवाला देते हुए संचालक कैमरा ऑन नहीं करते। वहीं चार कॉलेज ऐसे हैं, जिन्होंने एक सप्ताह बीतने के बाद भी नियंत्रण कक्ष से अपने कैमरे लिंक नहीं करवाए हैं। इसमें फिरोजाबाद के तीन और मथुरा का एक कॉलेज शामिल है। परीक्षा नियंत्रक डॉ. ओम प्रकाश ने बताया सीसीटीवी लिंक नहीं कराना बेहद आपत्तिजनक है। इन चारों पर 50–50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। साथ ही दो दिन के अंदर नियंत्रण कक्ष से सीसीटीवी कैमरा लिंक नहीं करवाने पर इन परीक्षा केंद्रों को निरस्त कर दिया जाएगा। परीक्षा नियंत्रक डॉ. ओम प्रकाश ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन किसी कीमत पर नकल नहीं होने देगा। नकल विहीन परीक्षा के लिए सभी परीक्षा केंद्रों को सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से नियंत्रण कक्ष से जुड़े रहने को कहा गया है।

नाला निर्माण में बाधक बने 25 अवैध निर्माण तोड़े, नागरिकों ने किया विरोध

गोरखपुर,(संवाददाता)। वार्ड नंबर 66 नेताजी सुभाष चंद्र बोसनगर में बुधवार को नगर निगम के प्रवर्तन दल ने नाला निर्माण में बाधक बन रहे 25 अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई का कुछ स्थानीय लोगों ने विरोध किया, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में विरोध का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वहीं, स्थानीय पार्षद और लोगों ने बिना नोटिस कार्रवाई का आरोप लगाया। अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह के निर्देश पर बुधवार को नगर निगम के प्रवर्तन दल के साथ काफी संख्या में पुलिस और पीएसी बल भी मौजूद रहा। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू होते देख मौके पर पार्षद अजय ओझा, पार्षद आरती सिंह, पार्षद प्रतिनिधि मोहन सिंह, गायक मनोज मिहिर समेत अन्य नागरिकों ने दस्ते की कार्रवाई का विरोध करना शुरू किया लेकिन उनकी एक नहीं चली। एक–एक कर चिह्नित सभी 25 अवैध निर्माण तोड़ दिए गए। नगर निगम की इस कार्रवाई से लोगों में आक्रोश है। स्थानीय पार्षद आरती सिंह के पति पार्षद प्रतिनिधि मोहन सिंह एवं पार्षद अजय ओझा ने आरोप लगाया कि नगर निगम ने किसी को नोटिस नहीं दिया है। दो दिन पहले सभी के मकानों पर निशान लगाए गए। उस दिन मौखिक रूप से कहा गया था कि अतिक्रमण स्वयं तोड़ लें अन्यथा निगम तोड़ देगा। पार्षद प्रतिनिधि मोहन सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि बसियाडीह नाला निर्माण में अधिकांश अल्पसंख्यक मोहल्ले आते थे,।

नई मशीनों को हरी झंडी दिखाकर नगर पालिका अध्यक्ष मनोरमा मौर्य ने किया रवाना

नगर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए आज से नई मशीनों से होगा कार्य

ब्यूरो प्रमुख

विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर नगर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए जाने के उद्देश्य से लगातार नगर पालिका प्रशासन प्रयासरत है। इस क्रम में नगर में की सफाई के लिए कुछ नई मशीनों को आज से प्रयोग में लाया जाएगा। नगर पालिका परिषद जौनपुर को शासन द्वारा 15वॉ वित्त आयोग निधि ा अन्तर्गत उपलब्ध करायी गयी ध नराशि से नगर को स्वच्छ एवं सुन्दर बनाने हेतु अध्यक्ष के निर्देशन में 1 जे0सी0बी0 मशीन 3 छोटा टैक्टर व पेयजलापूर्ति हेतु 5 पानी टैंकर खरीदा गया था । जिसका आज अध यक्ष श्रीमती मनोरमा मौर्या पालिका के अधिशासी अधिकारी पवन कुमार व अन्य अधिकारीगण द्वारा उपरोक्त वाहनों को हरी झण्डी दिखा कर जनहित में उपयोग करने के लिए वाहनों को रवाना किया गया। इससे पहले अध्यक्ष का नगर पालिका परिषद की पवन कुमार द्वारा बुके देकर स्वागत किया गया।इस अवसर पर उपस्थित जनता द्वारा अच्छी उपलब्धी बताते हुए अध्यक्ष एवं नगर पालिका की भूरि–भूरि प्रशंसा की गयी। इस अवसर पर अध्यक्ष प्रतिनिधि रामसूरत मौर्या, अधिशासी अधिकारी पवन कुमार, अवर अभियन्ता जल रागिनी मौर्या, अवध ेश यादव सफाई निरीक्षक, अनिल यादव प्र0 सफाई निरीक्षक, अवधेश कुमार राय कार्यालय अधीक्षक, अभिषेक श्रीवास्तव ट्रान्सपोर्ट प्रभारी,

मनोज यादव स्टोर कीपर, आशीष श्रीवास्तव लिपिक, अरविन्द यादव लिपिक, हर्षित मौर्या लिपिक, हामिद, नीरज श्रीवास्तव, प्रदीप यादव तथा अन्य पत्रकारधमिडिया बन्धु व नागरिकगण उपस्थित रहे।

भाषा विवि के छात्रों का अमूल बनास डेयरी का दौरा

लखनऊ,(संवाददाता)। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ के बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग विभाग के बी.टेक छात्रों ने किया अमूल बनास डेयरी का दौरा किया गया। प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालय से विभिन्न शैक्षणिक दौरों का आयोजन होता है इसी श्रृंखला में ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ के बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग विभाग के बी.टेक छात्रों ने औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत लखनऊ स्थित प्रसिद्ध अमूल बनास डेयरी का दौरा किया। अमूल बनास डेयरी की टीम ने छात्रों का गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें संयंत्र के संचालन, उत्पादन प्रक्रियाओं और गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र की जानकारी दी। छात्रों ने डेयरी संयंत्र के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया, जिसमें दूध प्रसंस्करण इकाइयां, पैकेजिंग लाइन, कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं आदि शामिल हैं। उन्हें उत्पादन और वितरण में उपयोग की जाने वाली उन्नत तकनीकों और मशीनों से परिचित कराया गया। इस दौरे के बारे में बात करते हुए विभागाध्यक्ष डॉ. आर.के. त्रिपाठी ने कहा कि इस औद्योगिक दौरे ने हमारे छात्रों को डेयरी उद्योग में आधुनिक औद्योगिक प्रक्रियाओं और नवीन तकनीकों की व्यावहारिक समझ प्रदान की। अमूल बनास डेयरी के प्रबंधन ने भी अपनी स्थिरता प्रथाओं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और ग्रामीण विकास में डेयरी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जानकारी साझा की। दौरे का समापन एक संवादात्मक सत्र के साथ हुआ, जिसमें छात्रों ने विशेषज्ञों के साथ करियर के अवसरों, नवीन प्रथाओं और डेयरी उद्योग में चुनौतियों पर चर्चा की। इस तरह के औद्योगिक दौरे भविष्य के पेशेवरों को गढ़ने और उन्हें अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करने में अहम भूमिका निभाते हैं।

टूरिज्म स्थलों के आसपास होमस्टे को आय के स्रोतों से जोड़ने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कराया गया

बेववेवर नेस्ट्स के सहयोग से टूरिज्म स्थलों के आसपास होम स्टे को बढ़ावा देने के लिए शोध किया जायेगा–जयवीर सिंह

लखनऊ,(संवाददाता)। विदेशों की तर्ज पर टूरिज्म स्थलों के आसपास होम स्टे को लोकप्रिय बनाने तथा बुनियादी सुविधायें सृजित करने के लिए विस्तार से जानकारी एकत्र की जायेगी। इसका उद्देश्य होम स्टे के आसपास के वासिंदों की आमदनी बढ़ाना है। साथ ही होम स्टे का लाभ उठाने वाले पर्यटकों को स्थानीय जीवन की विविध गतिविधियों, परम्परा, विरासत तथा वेश भूषा, रहन सहन एवं व्यंजन आदि के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना है। ताकि पर्यटक स्थानीय जीवन को नजदीक से समझ सके और एक अविस्मरणीय अनुभूति लेकर वापस लौटे। इसके लिए गत दिनों पर्यटन विभाग एवं बेववेवर नेस्ट्स लखनऊ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। यह जानकारी प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि "हमारा उद्देश्य होमस्टे क्षेत्र में व्याप्त चुनौतियों और संभावनाओं को समझते हुए उसके विकास हेतु उचित कदम उठाना है। इससे पर्यटन और स्थानीय व्यवसाय को काफी लाभ होगा।" यह शोध कार्य उत्तर प्रदेश के पर्यटन के दृष्टिकोण को नए आयाम देगा और होमस्टे व्यवसाय में नई संभावनाओं को उजागर करेगा। इस साझेदारी से उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में होमस्टे सुविधाओं का न केवल विस्तार होगा बल्कि उनके प्रबंधन और गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। श्री जयवीर सिंह ने बताया कि यह शोध कार्य आगरा, वाराणसी और आसपास के इको टूरिज्म स्थलों में होमस्टे व्यवसाय को बढ़ावा देने, उसकी गुणवत्ता में सुधार लाने, पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने और स्थानीय पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए किया जा रहा है। इस समझौते का उद्देश्य न केवल पंजीकृत होमस्टे को सुधारना है, बल्कि गैर–पंजीकृत होमस्टे को भी पर्यटन के मानकों में लाना है। उन्होंने बताया कि विदेशों में होम स्टे काफी लोकप्रिय हो रहा है, इससे ग्रामीण अंचलों तथा पर्यटन के आसपास के निवासियों को आय के साधन उपलब्ध हो रहे हैं, इसकी सफलता को देखते हुए उ0प्र0 में इसे लागू करने और सफल बनाने के लिए शोध कराने का निर्णय लिया गया है।

खेल मंत्री ने संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित पदयात्रा को हरी झण्डी दिखाकर शुभारम्भ किया

लखनऊ,(संवाददाता)। उ0प्र0 के खेल एवं युवा कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गिरीश चन्द्र यादव ने आज 75 वें संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर राजधानी में आयोजित एक पदयात्रा को हरी झण्डी दिखाकर शुभारम्भ किया। इस अवसर पर प्रमुख सचिव, युवा कल्याण एवं खेल, श्री आलोक कुमार द्वितीय, सचिव, युवा कल्याण एवं खेल तथा महानिदेशक, युवा कल्याण, श्री सुहास एल.वाई. विशेष सचिव, युवा कल्याण, श्री सुनील कुमार वर्मा, संयुक्त निदेशक, श्री अशोक कुमार कनौजिया एवं अन्य विभागीय अधिकारी गण उपस्थित रहे एवं पदयात्रा में प्रतिभाग किये। पदयात्रा 1090 चौराहा से प्रारम्भ होकर अम्बेडकर पार्क गोमती नगर के परिसर में स्थित मुख्य स्थल पर समाप्त हुई। राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा डा० भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति पर पुष्पार्पण करने के उपरान्त पदयात्रा समापन स्थल पर एकत्रित युवाओं को सम्बोधित करते हुए संविधान दिवस की महत्ता के विषय में बताया गया। तदोपरान्त संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया गया। उन्होंने कहा कि 26 नवम्बर का दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का संविधान, भारत के गौरव एवं भारत की एकता का प्रतीक है। संविधान दिवस का उद्देश्य डॉ भीमराव अम्बेडकर के विचारों और अवधारणाओं को प्रसारित करने के साथ–साथ संविधान के प्रति नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया जाना है। गिरीश चन्द्र यादव द्वारा युवाओं को संबोधित करते हुए मेरा संविधान, मेरा स्वाभिमान, संविधान है तो भारत है, भारत का संविधान अधिकारों का प्रतीक व कर्तव्यों का पथ है, संविधान से जुड़े अपने कर्तव्यों को समझने, संविधान की 75वीं वर्षगांठ समारोह मनाने के साथ ही यह कार्यशील होने का आह्वान किया गया, लोगों और समुदायों को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सार्थक सहयोग देने के योग्य बनाने के उद्देश्य से उन्हें शिक्षित और संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने की बात कही गयी। पदयात्रा में युवा कल्याण विभाग के युवक एवं महिला मंगल दल के युवा, नेहरू युवा केन्द्र संगठन के युवा, प्रान्तीय रक्षक दल के बैण्ड, खेल विभाग के खिलाड़ी एवं राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े छात्र–छात्राओं सहित 2,000 से अधिक युवाओं द्वारा प्रतिभाग किया गया।

हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव : 11वीं सांस्कृतिक संध्या में गरबा नृत्य ने दशकों का मन मोहा

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ । स्मृति उपवन बंग्ला बाजार में आयोजित माँ गायत्री जन सेवा संस्थान एवं नीशू वेलफेयर फाउंडेशन के तत्वाधान में हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव में शुक्रवार शाम आज के बतौर मुख्य अतिथि सदस्य विधान परिषद मुकेश शर्मा एवम अध्यक्ष अरुण प्रताप सिंह व गुंजन वर्मा द्वारा सांस्कृतिक संध्या का शुभारम्भ दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। सांस्कृतिक संध्या की शुरूआत नेचुरल टच वेलफेयर सोसायटी द्वारा अध्यक्ष– स्मृति शर्मा महाराष्ट्र लोक–देव श्री गणेशा, बांग्ला– लोकगीत,राजस्थान– मैशअपध कालबेलिया, गुजराती– ढोलिडा ढोल रे वागड़ से प्रस्तुती दी गई जिसमें कुल– 53 प्रतिभागी (आर्यकन्या पाठशाला इंटर स्कूल, आरबीएन ग्लोबल स्कूल) रहें। चार प्रस्तुति में महाराष्ट्र गणेश उपासना के साथ गणेश जी स्थापना हुई, दूसरे पर बंगला, तीसरे पर राजस्थान चौथे पर गुजरात अपने प्रसिद्ध गरबा के साथ

प्रस्तुति देकर भारत को अनेकता में एकता को दर्शाया। अन्त में सब प्रदेश मिल कर मंच पर शामिल हुऐ और गणेश जी को वापस उनके धाम जाने का उत्सव किया। भारत के अनेकों राज्य हैं और उनके अपने–अपने उत्सव हैं और जब उत्सव की बात आती है तो मन हर्ष और उल्लास से भर जाता है। पूजा में सर्वप्रथम गणेश जी की उपासना की जाती है। तत्सत सेवा संस्थान सीतापुर के द्वारा सांस्कतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसका संचालन अलीशा मेराज के द्वारा किया गया। तत्सत टीम के डायरेक्टर अभय श्रीवास्तव् के साथ आराधना सिंह, यस्वि चौरसिया,अम्बर श्रीवास्तव, शिखा वर्मा, नाहिद नाज ,आरुषि अग्रवाल,तौकीर खान,यासीन इब्ने उमर,अंकिता सिंह, खुशि राठौर ने शानादार प्रस्तुती देकर दर्शको को आकर्षित किया। यस्वि ने सत्यम शिवम सुंदरम...... अभय श्रीवास्तव ने सुहांनी चांदनी राते.... कभी कभी मेरे दिल ख्याल.... शिखा ने गली मै आज चाँद निकला... गीत से दर्शन मंत्रमुग्ध हुए। इस अवसर पर महोत्सव समिति के रणवीर सिंह ,विनय दुबे, हेमू चौरसिया आदि उपस्थित रहे। मंच का संचालन प्रदीप शुक्ला एवम मनीष पंडित ने किया।

पीएचडीसीसीआई ने प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण सुरक्षा पर एक इंटरैक्टिव सम्मेलन का आयोजन किया

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ । उत्तर प्रदेश चौप्टर ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से हरित उद्योग की ओर : प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण सुरक्षा पर एक इंटरैक्टिव सम्मेलन का आयोजन किया है। सम्मेलन के मुख्य अतिथि श्री अरुण कुमार सक्सेना, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), वन एवं पर्यावरण, प्राणी उद्यान, जलवायु परिवर्तन–उत्तर प्रदेश थे। मुख्य अतिथि श्री अरुण कुमार सक्सेना, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), वन और पर्यावरण, प्राणी उद्यान, जलवायु परिवर्तन–उत्तर प्रदेश ने उपस्थित लोगों को हरित बुनियादी ढांचे की दिशा में सामूहिक रूप से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। माननीय राज्य मंत्री ने कहा इसमें कोई संदेह नहीं है कि पर्यावरण हमारे अस्तित्व का एक अनिवार्य हिस्सा है, जो जीविकोपार्जन के लिए हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर निर्भर करता है। औद्योगीकरण और पर्यावरण साथ–साथ चलते हैं। पर्यावरण और औद्योगीकरण, दोनों क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए हमें हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाने की जरूरत है, जो हमें सतत विकास लक्ष्य की राह पर ले जाएं। विशिष्ट अतिथि डॉ. रवीन्द्र प्रताप सिंह, अध्यक्ष–उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, श्री संजीव कुमार सिंह, आईएफएस–सदस्य सचिव–उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, श्री कमल कुमार, क्षेत्रीय निदेशक–केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने निवारक उपायों के बारे में चर्चा की । एएमए हर्बल के को–फाउंडर और सीईओ, श्री यावर अली शाह ने कहा, ष्आधुनिक समय की आवश्यकताओं के अनुसार ग्रीन इंडस्ट्री की परिभाषा को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। ग्रीन इंडस्ट्री का मतलब एक ऐसे उद्योग से है जो पर्यावरण के अनुकूल हो। एक पर्यावरण–अनुकूल उद्योग तभी सफल हो सकता है, जब पर्यावरण को सभी क्षेत्रों में प्राथमिकता दी जाए। आने वाले वर्षों की योजनाएं मुनाफे और स्थिरता, दोनों पर केंद्रित होनी चाहिए। यह तीन प्रमुख स्तंभों – अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, और सामाजिक प्रभाव – पर आधारित है। अगर इन तीनों में से किसी एक को नजरअंदाज किया गया, तो उद्योग स्थायी नहीं रह सकता। वह मुनाफा कमा सकता है, लेकिन सही मायनों में स्थिरता तभी आती है जब मुनाफे को कार्बन उत्सर्जन में कमी के साथ संतुलित किया जाए। उद्योग का अंतिम लक्ष्य कार्बन–तटस्थ स्थिति हासिल करना होना चाहिए। हमारे उद्योग और व्यापार की परिभाषा इसी संतुलन में है, जहां मुनाफा पर्यावरणीय स्थिरता, आर्थिक विकास और समाज में योगदान की दिशा में प्रगति का प्रतीक हो। यही एक आदर्श ग्रीन इंडस्ट्री की परिभाषा है। हम मानते हैं कि एक पर्यावरण–संवेदनशील उद्योग तभी सफल हो सकता है जब पर्यावरण को सभी क्षेत्रों में एकीकृत करके शामिल किया जाए।ष इस सत्र में कई अन्य सरकारी अधिकारियों और उद्योग जगत के उद्योगपतियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। डॉ. रवीन्द्र प्रताप सिंह, अध्यक्ष–उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

श्री संजीव कुमार सिंह, आईएफएस–सदस्य सचिव–उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, श्री कमल कुमार–क्षेत्रीय निदेशक–केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, श्री सुरेंद्र कुमार जयसवाल, अध्यक्ष–उत्तर प्रदेश होटल एवं रेस्तरां एसोसिएशनय अध्यक्ष– होटल एंड रेस्तरां एसोसिएशन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, वी.पी.– फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्तरां एसोसिएशन ऑफ इंडियाय श्री गिरिजा शंकर, प्रबंध निदेशक– ग्रीन गैस लिमिटेड, श्री सनोज कुमार गुंजन, एजीएम– सिडबी, लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय, श्री एल के झुनझुनवाला, वरिष्ठ सदस्य यूपी चौप्टर, पीएचडीसीसीआई और अध्यक्ष– के एम शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, श्री राजेंद्र संखे, सीओओ– इंडोरामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेडय श्री संजीव सरीन, अध्यक्ष–रिटेल राज्य उप–समिति, यूपी चौप्टर–पीएचडीसीसीआई और वरिष्ठ केंद्र निदेशक (मॉल और हॉस्पिटैलिटी) नॉर्थ, द फीनिक्स मिल्स लिमिटेडय श्री आशीष मोहन विग– अध्यक्ष– औद्योगिक संबंध एवं मानव संसाधन समिति, पीएचडीसीसीआईय डॉ. जतिंदर सिंह, उप महासचिव, पीएचडीसीसीआईय श्री अतुल श्रीवास्तव– क्षेत्रीय निदेशक, यूपी स्टेट चौप्टर पीएचडीसीसीआई और कई अन्य प्रसिद्ध उद्योगपति उपस्थित थे।

औद्योगिक प्रदूषण हवा, पानी और मिट्टी में प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है, औद्योगिक प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैंरू

1पानी का उपयोग कम करेंरू पानी का पुनरू उपयोग और पुनर्चक्रण करें, और वर्षा जल का संचयन करें

2 अपशिष्टों का उपचार करेंरू गर्म पानी और अपशिष्टों को नदियों और तालाबों में छोड़ने से पहले उनका उपचार करें

3 वायु प्रदूषण कम करेंरू इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर्स, फैब्रिक फिल्टर, स्क्रबर्स और इनर्शियल सेपरेटर के साथ स्मोकस्टेक्स फिट करें

4 नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करें।

5 ऊर्जा दक्षता में सुधाररू ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए उपकरणों को अपग्रेड करें और नई तकनीकों को अपनाएं

6 ध्वनि प्रदूषण कम करेंरू शोर उत्पन्न करने वाले उपकरणों के लिए साइलेंसर का उपयोग करें

7 सही जगह पर निर्माण करेंरू फैक्टरियों का निर्माण उन स्थानों पर करें जो उपयुक्त हों

8 कचरे का विश्लेषण करेंरू कारखाने के कचरे का विश्लेषण करें और उसका उचित उपचार करें

9 पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करेंरू कारखानों से पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन कराएं

10 कानून लागू करेंरू कारखाने के कचरे को रोकने के लिए कानूनों और प्रवर्तन का उपयोग करें

इस सम्मेलन में हरित पहल की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हरित उद्योग के कई परिप्रेक्ष्यों पर विचार–विमर्श किया गया और यह भी बताया गया कि बुनियादी ढांचा क्षेत्र 1 ट्रिलियन डॉलर की राज्य अर्थव्यवस्था में कैसे योगदान दे सकता है। विषय विशेषज्ञों ने इस विषय पर विचार–विमर्श किया और राज्य के औद्योगिक और बुनियादी ढांचे क्षेत्र में आम चुनौतियों और उनके लिए व्यवहार्य समाधानों को सामने रखा, कॉन्क्लेव में बड़ी संख्या में भागीदारी देखी गई जिसमें उद्योग, होटल, अस्पताल, शिक्षा जगत के प्रतिनिधि, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ पत्रकार, नीति निर्माता, विचारक नेता, वित्तीय संस्थान और कई अन्य शामिल थे।

एचआईवी/एड्स पर मीडिया के लिए जागरूकता कार्यशाला का आयोजन

उत्तर प्रदेश में 1.20 लाख लोग ले रहे एचआईवीध्एड्स का उपचार

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ ।उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी (न्ै।ब्ै) के तत्वावधान में सोसाइटी सभागार में एचआईवीध्एड्स पर मीडिया प्रतिनिधियों के लिए जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य एचआईवीध्एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने और इससे जुड़े सामाजिक भेदभाव को खत्म करने में मीडिया की सक्रिय भूमिका को रेखांकित करना था। कार्यशाला की शुरुआत करते हुए संयुक्त निदेशक (प्रिवेंशन) रमेश श्रीवास्तव ने कहा कि एचआईवीध्एड्स के प्रति समाज में फैली भ्रांतियों को दूर करना और सही जानकारी को जन–जन तक पहुंचाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने यह भी बताया कि इस दिशा में मीडिया का योगदान बेहद महत्वपूर्ण है और जागरूकता बढ़ाने में मीडिया एक प्रभावी माध्यम बन सकता है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में अनुमानित 1.97 लाख लोग एचआईवी संक्रमित हैं, जिनमें से लगभग 1.20 लाख लोग समस्त जनपदों में स्थापित एआरटी केंद्रों के माध्यम से उपचार प्राप्त कर रहे हैं। कार्यशाला में मौजूद डॉ. गीता अगरवाल, संयुक्त निदेशक–बीएसडी ने बताया कि 2030 तक एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, और इस दिशा में वर्ष 2025–26 बेहद महत्वपूर्ण है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए नए संक्रमणों में 80ः की कमी लाना, एड्स से होने वाली मृत्यु दर को घटाना, और एचआईवी संक्रमित माताओं से बच्चों में संक्रमण का खतरा पूरी तरह समाप्त करना प्रमुख प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में एड्स से संबंधित सुविधाओं की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि राज्य में एचआईवी जांच के लिए 399 इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर (ICTC) उपलब्ध हैं। इसके अलावा, 52 एआरटी (एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी) केंद्रों पर उपचार की सुविधा दी जा रही है। राज्य में 35 संपूर्ण सुरक्षा केंद्र और 115 एसटीआई / आरटीआई (यौन संचारित संक्रमणध्प्रजनन मार्ग संक्रमण) केंद्र भी कार्यरत हैं, जो एड्स और इससे जुड़ी अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मददगार साबित हो रहे हैं। एड्स के खतरों के बारें में जानकारी देते हुए डॉ. एके सिंघल, संयुक्त निदेशक (केयर सपोर्ट एवं उपचार सेवा) ने बताया कि संक्रमण का सबसे बड़ा कारण असुरक्षित शारीरिक संबंध है, जो 83प्रतिशत मामलों के लिए जिम्मेदार है। वहीं, लगभग 6.3प्रतिशत मामलों में यह संक्रमण संक्रमित सुई के उपयोग से फैलता है। कार्यक्रम में डॉ. चित्रा सुरेश (संयुक्त निदेशक–एसटीआइ) ने सुरक्षा क्लीनिक और अन्य बुनियादी सेवाओं से जुड़ी जानकारी साझा की। इसके अलावा, उप निदेशक (आईईसी) पवन चंदेल और सहायक निदेशक (डीएंडपी) अनुज दीक्षित भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विभिन्न मीडिया कर्मियों ने सक्रिय भागीदारी की। अंत में एक खुली चर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने अपनी शंकाओं और सुझावों को खुलकर साझा किया।

भारतीय संविधान केवल अधिकार ही नहीं प्रदान करता बल्कि कर्तव्यों के दायित्व का बोध भी कराता है

लखनऊ,(संवाददाता)। भारतीय संविधान केवल अधिकार ही नहीं प्रदान करता बल्कि कर्तव्यों के दायित्व का बोध भी कराता है। आज हम 75वां संविधान दिवस मना रहे हैं जो कि संविधान का अमृत काल है। आजादी के बाद हमारा संविधान लिखा गया इसमें विभिन्न प्रकार के परिवर्तन किये गए और जो स्वरूप हमें आज मिला है उसने हमें जीने की कला सिखाई है। समाज कल्याण मंत्री ने कहा कि भारत का संविधान भारत के लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समतावादी ढांचे को परिभाषित करने वाला आधाभूत दस्तावेज है। भारतीय संविधान अपने नागरिको के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित करता है। ये बातें समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री असीम अरूण ने भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने के फलस्वरूप संविधान को अंगीकृत किए जाने की तिथि 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर संविधान की विशिष्टताओं एवं उनमें वर्णित मौलिक कर्तव्यों की महत्ता के प्रति भागीदारी भवन स्थित छत्रपति साहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण है।

60 वर्षीय सरदार सिंह ने जीती कैंसर से जंग

स्टेज 4 कैंसर को दी मात , कैंसर रोगियों के लिए जगाई उम्मीद की नई किरण

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

ग्रेटर नोएडा। गाजीपुर के रहने वाले 60 वर्षीय सरदार सिंह यादव स्टेज 4 कैंसर को मात देकर उन कैंसर रोगियों के लिए उम्मीद की कारण जगाई है। सरदार सिंह बोन बोन मैरो में हॉजकिन लिम्फोमा कैंसर से जूझ रहे थे। सही जांच और इलाज के बाद अब वह पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उनका इलाज फोर्टिस– ग्रेटर नोएडा में चला, जहां के लिए यह केस चिकित्सीय समर्पण और कुशलता की एक मिसाल है। इस केस से ये पता चलता है कि एडवांस स्टेज के कैंसर का उपचार संभव है। सरदार सिंह जी पिछले 6 महीनों से बुखार, कमजोरी और शरीर में दर्द से गुजर रहे थे, इस दौरान कई डाक्टरों को उन्होंने दिखाया लेकिन कई जांच और इलाज के बाद भी उनको राहत नहीं मिली इसके बाद वो फोर्टिस ग्रेटर नोएडा इलाज के लिए पहुंचे। श्री यादव जब यहाँ आए तब वह कई लिम्फ नोड्स में सूजन और प्लेटलेट्स में खघ्तरनाक स्तर की कमी से जूझ रहे थे। लिम्फ नोड्स बायोप्सी से कोई सटीक नतीजे नहीं मिलने के बावजूद फोर्टिस ग्रेटर नोएटा की मेडिकल ऑन्कोलॉजी टीम ने बोन मैरो की जाँच की। आमतौर पर हॉजकिन लिम्फोमा और डीएलबीसीएल (सबसे सामान्य प्रकार के नॉन–हॉजकिन लिम्फोमा) के मामलों में, पीईटी–सीटी रिपोर्ट के आधार पर बोन मैरो की जाँच से बचा जा सकता है। अगर पीईटी–सीटी रिपोर्ट में बोन मैरो में कैंसर दिखे तो आगे बायोप्सी की जरूरत ही नहीं होती और अगर पीईटी–सीटी रिपोर्ट में बोन मैरो सुरक्षित है तो बिना बायोप्सी के ही बोन मैरो को सुरक्षित माना जाता है, लेकिन जांच में नतीजे नहीं आने की वजह से चिकित्सकों की टीम ने जांच के अगले स्तर पर ले जाना उचित समझा। जिसमें जाकर कैंसर की पुष्टि हुई। फोर्टिस ग्रेटर नोएडा में एसोसिएट कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजी, डॉ. अभिषेक श्रीवास्तव ने कहा, "स्टेज 4 में बोन मैरो के कैंसर के साथ हॉजकिन लिम्फोमा बहुत आम है, लेकिन श्री यादव के केस में यह असामान्य और आक्रामक रूप में मौजूद था। सीएचएल यानी क्लासिकल हॉजकिन लिम्फोमा से आमतौर पर युवा प्रभावित होते हैं, लेकिन श्री यादव जैसे बुजुर्ग मरीजों में स्वास्थ्य से सम्बंधित अन्य समस्याओं की वजह से हॉजकिन लिम्फोमा के केस की जटिलताएँ बढ़ जाती हैं। बोन मैरो में हॉजकिन लिम्फोमा कैंसर होने का मतलब है कि कैंसर लिम्फ नोड्स से बाहर फैल चुका है, जिससे थकान, खून की कमी, और संक्रमण की संवेदनशीलता का बढ़ना जैसे गम्भीर लक्षण पैदा होते हैं।" फोर्टिस ग्रेटर नोएडा की मेडिकल ऑन्कोलॉजी कंसल्टेंट, डॉ. सरिका बंसल ने बताया कि श्री यादव ने यहां इलाज शुरू कराने से पहले अन्य कई प्रतिष्ठित अस्पतालों में परामर्श लिया था, लेकिन कोई जाँच रिपोर्ट ऐसी नहीं थी जिससे सही नतीजे पर पहुँचा जा सके। इस केस से पता चलता है कि अगर लक्षण साफ न हों तो स्टैण्डर्ड प्रोसीजर से आगे बढ़कर जाँच के तरीकों का इस्तेमाल कितना जरूरी हो जाता है। बोन मैरो की जांच से हमें श्री यादव की स्थिति की सटीक जाँच और फिर उसके हिसाब से इलाज करने में मदद मिली, जिससे हमें सही नतीजे मिले। जाँच के नतीजों के बाद, मेडिकल ऑन्कोलॉजी टीम ने एक उपचार के लिए एक विस्तृत योजना बनाई, जिसमें सभी ऐसी जटिलताओं को ध्यान में रखा गया जिनके होने की सम्भावना थी। इसमें एक बड़ा खतरा माइलोसप्रेशन का होता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें बोन मैरो की गतिविधियाँ कम हो जाती हैं, जिससे संक्रमण और रक्तस्राव का खतरा बढ़ जाता है। मार्च में श्री यादव की पहली कीमोथेरेपी शुरू की गई और उनको लगातार मॉनिटर किया गया। प्लेटलेट्स के लिए कई ट्रांसफ्यूजन किए गए और एंटीबायोटिक्स के जरिए संक्रमण से बचाव की व्यवस्था की गई। श्री यादव के साथ कीमोथेरेपी के कुल छह साइकल पूरे किए गए। दो साइकल के बाद हुए पीईटी–सीटी स्कैन में थोड़ा सुधार दिखाई दिया और चार साइकल के बाद हुई जाँच में बोन मैरो में एक भी असामान्य सेल नहीं पाई गई। उनकी पूरी रिकवरी हो चुकी है और वे अब हर महीने फॉलो–अप के लिए अस्पताल आते हैं। उपचार के दौरान श्री सरदार सिंह यादव ने कहा, "मैं अपने डॉक्टरों, अस्पताल के मेडिकल स्टाफ का बहुत आभारी हूँ, जो हर कदम पर मेरे साथ रहे। एक वक्घ्त था जब लगा था कि मैं जिंदगी की ये जंग हार जाऊँगा, लेकिन उनके समर्पण और विशेषज्ञता ने मुझे हर समय पर आगे बढते रहने की हिम्मत दी। यह सफर आसान नहीं था, लेकिन सटीक इलाज, उम्मीद और आत्मविश्वास के साथ हमने इस मुश्किल को हराने में

कामयाबी पाई। मैं चाहता हूँ कि मेरी यह यात्रा अन्य लोगों के लिए प्रेरणा बने और उन्हें यह विश्वास हो कि चिकित्सा की शक्ति से हम किसी भी चुनौती पर जीत हासिल कर सकते हैं। 'फोर्टिस ग्रेटर नोएडा के सीईओ, डॉ. प्रवीण कुमार' ने बताया, " हम उन्नत चिकित्सा सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और मरीजों की देखभाल में लगातार बेहतर करते रहने की हमारी कोशिश हमें सफलता दिलाती है। हमें मालूम है कि मुश्किल से मुश्किल केस में समय पर जाँच और सही उपचार बहुत जरूरी है और हमारी टीम की यह कोशिश हमारे अस्पताल की इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि हम मरीजों के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं।"

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक
श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव
मो0 - 7007415808, 9628325542, 9415034002
RNI NO - UPHIN/2022/86937
Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।